

9 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, हत्या उज्जैन में पड़ोसी ने बोरी में भरकर मोगरी से पीटा; परिजन से कहा- छत से गिर गई

उज्जैन (नप्र)। मध्यप्रदेश में उज्जैन के खाचरोद में रेप करने में नाकाम होने पर 9 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मासूम रविवार को नानी के घर आई थी। पड़ोस में ही रहने वाले शख्स ने पहले दुष्कर्म करने की कोशिश की। चिह्नने पर उसने बच्ची को बोरी में बंद कर दिया। फिर मोगरी से लगातार वार किए।

गंभीर हालत में बच्ची को रतलाम के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई।

बच्ची के छत से गिरने का बहाना बनाया- खाचरोद पुलिस ने बताया कि बच्ची रविवार को स्कूल की छुट्टी होने के कारण अपनी दो बड़ी बहनों के साथ नानी के घर आई थी। नानी और बड़ी बहनें रविवार दोपहर को छत पर बैठी थीं। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। काफी देर तक बच्ची घर नहीं आई तो नानी ने उसकी बहन को भेजा लेकिन वह कहीं नहीं दिखी।

शाम करीब 5.45 बजे पड़ोस में रहने वाला रियाज खान अपने घर के अंदर से



रियाज खान, आरोपी

बेहोश बच्ची को उठाकर लाया। कहा- लड़की ऊपर से गिर गई है।

बच्ची का मुंह सूजा था। सिर, नाक,

आंख पर चोट लगी थी। खून निकल रहा था। परिजन उसे लेकर खाचरोद अस्पताल पहुंचे। यहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे रतलाम रेफर

कर दिया गया था। डॉक्टर की रिपोर्ट से पटने का खुलासा हुआ- खाचरोद एसडीओपी आकांक्षा बिछोटे ने कहा- डॉक्टर से बात करने पर पता चला कि बच्ची के शरीर पर गिरने के निशान नहीं हैं। उसे किसी हार्ड चीज से मारा गया है। इस पर पुलिस ने डॉंग स्कूड और फोरेंसिक टीम को भेजकर रियाज के घर से सबूत इकट्ठा किए। इसके बाद रियाज खान से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। उसने बताया कि घर में कोई नहीं था। बच्ची घर में आई तो उसे अकेला पाकर गुलत काम करने का प्रयास किया। वो चिह्नने लगी। हाथ-पैर पटकने लगी। गुस्से में आकर रियाज ने उसे धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिरकर बेसुध हो गई। इसके बाद रियाज ने उसे बोरी में डालकर मोगरी से पीटा। मरा समझकर घर से बाहर निकल गया। बाद में लौटा तो देखा कि बच्ची की सांस चल रही है। रियाज बच्ची को उसकी नानी के पास ले गया। उसके छत से गिरने की झूठी कहानी सुनाई।

गोवा अग्निकांड: लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से लाया गया दिल्ली

● गोवा पुलिस ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, 25 लोगों की मौत के बाद भागे थे

नई दिल्ली (एजेंसी)। गोवा के नाइट क्लब 'बिर्च बाय रोमियो लेन' अग्निकांड मामले में मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड से दिल्ली लाया गया है। भारतीय सुरक्षा अधिकारी दोनों भाइयों के साथ मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरे। दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस की एक टीम ने दोनों को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड की इजाजत मिलते ही पुलिस दोनों को लेकर गोवा जाएगी। सौरभ और गौरव लूथरा बिर्च नाइट क्लब के मालिक हैं। क्लब में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत

हो गई थी। घटना के बाद दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे। थाईलैंड पुलिस ने 11 दिसंबर को फुकेट में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया। आज सुबह उन्हें बैंकॉक से भारत डिपोर्ट किया गया था। सूत्रों के अनुसार, 9 दिसंबर को थाई अधिकारियों को पता चला कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जिन भाइयों को ढूढ़ रही है, वे फुकेट में छिपे हैं। भारतीय एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद थाई अधिकारियों ने पहले ही होटलों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। 11 दिसंबर को जब दोनों भाई होटल से बाहर खाना खाने के लिए निकले तो थाई इमिग्रेशन और पुलिस अधिकारियों ने उनकी पहचान और यात्रा की डिटल्स वेरिफाई की और पकड़ लिया।



हाईवे पर पिकअप की टक्कर से शिक्षक मां-बेटे की मौत खरगोन में नशे में था ड्राइवर, हादसे के बाद गिरफ्तार

खरगोन (नप्र)। खरगोन में चित्तौड़ाढ़-भुसावल राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार लोडिंग पिकअप वाहन ने दो बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में शिक्षक मां-बेटे की मौत हो गई, बेटे ने मौके पर दम तोड़ा। जबकि गंभीर रूप से घायल आश्रम अधीक्षक शिक्षक मां ने निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा।

हादसा मंगलवार सुबह 10.45 बजे का है। बाइक सवार शिक्षक ऋतुराज बिल्वे (25) निवासी ब्रजविहार खरगोन मां मधु के साथ स्कूल जा रहे थे। जामली गांव के पास सामने से तेज रफ्तार में आ रहे पिकअप ने एक के बाद एक दो बाइक को चपेट में ले लिया। हादसा भीषण था कि शिक्षकों की बाइक का अगला पहिया बाहर निकल गया। ऋतुराज की मौके पर मौत हो गई।

सूचना पर मौके पर खरगोन कोतवाली पुलिस पहुंची। ग्रामीणों की मदद से गंभीर घायलों को एम्बुलेंस की मदद से खरगोन जिला अस्पताल भिजवाया गया। मृतक ऋतुराज अपनी मां मधुबाई और साथी अतिथि शिक्षक प्रदीप तोताराम निवासी डालका के साथ रायसागर स्कूल जा रहे थे। मधुबाई बिस्टान कन्या आश्रम में शिक्षिका हैं।

घायल प्रदीप का कहना था कि पिकअप का ड्राइवर शराब के नशे में था। तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ने दो

बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद खरगोन कोतवाली पुलिस ने पिकअप जन्त किया। ड्राइवर की गिरफ्तार कर लिया है।

एसडीओपी रोहित लखारे ने कहा कि जामली के पास पिकअप की टक्कर में शिक्षकों की मौत हुई है। पिकअप जन्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।

सिवनी में टायर फटने से यात्री बस पलटी चालक सहित 12 से अधिक यात्री घायल; जबलपुर से नागपुर जा रही थी बस

सिवनी (नप्र)। सिवनी जिले के लखनादैन थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-34 पर चौथा मील के पास दोपहर लगभग 2 बजे एक यात्री बस का टायर फटने से बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में चालक सहित 12 लोगों से अधिक यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, रॉयल बस जबलपुर से नागपुर की ओर जा रही थी। चौथा मील के पास पहुंचते ही अचानक बस का टायर फट गया, जिससे बस सड़क पर पलट गई।

घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया-घटना की सूचना प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही लखनादैन पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनादैन थाना प्रभारी कौरत प्रसाद दुबे ने बताया कि बस पलटने से कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी। पुलिस फिलहाल घटना की जांच कर रही है और घायलों के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। जिस स्थान पर यह हादसा हुआ वहां लोगों व वाहनों का आना जाना अधिक होता है। घटना के समय लोग या वाहन मौजूद होते तो बड़ा हादसा हो सकता था।

भारतीय सीमा पर चीनी सेना की है खतरनाक प्लानिंग

पाकिस्तान का साथ पीएलए की 'गोल्डन विंडो' चाल का खुलासा

इस्लामाबाद/बीजिंग (एजेंसी)। चीन की सेना पीएलए के पश्चिमी थिएटर कमांड और पाकिस्तानी सेना ने वॉरियर पीएलए नाम से एक संयुक्त सैन्य



अभ्यास किया है। पाकिस्तान में दोनों सेनाओं का यह अभ्यास 14 दिसंबर को खत्म हो गया। इस दौरान चीन और पाकिस्तान की सेनाओं ने संयुक्त रूप से

आतंकवाद निरोधक अभियान का अभ्यास किया। चीनी सेना ने एक बयान जारी करके कहा कि इस अभ्यास के दौरान क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखने की क्षमता का परीक्षण किया गया। साथ ही पाकिस्तान और चीन की परंपरागत दोस्ती को और ज्यादा मजबूत किया गया। चीन की सेना न केवल पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर दबाव बना रही है, बल्कि भारतीय सीमा के पास उसने ऐसी तैयारी कर ली है कि मात्र 24 से 48 घंटे में वह जंग के लिए अपने सैनिकों को तैनात कर सकती है। स्वराज्य की रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए के लगातार हो रहे सैन्य अभ्यास से सेना के टेक्स्टबुक से यह खुलासा होता है।

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल को राहत

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और 5 अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर सज़ा न लेने से इनकार कर दिया। ईडी ने कहा है कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी। राजज एवेन्यू कोर्ट के



स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में दारिखल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है, न कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अनुसूचित अपराध से जुड़े एफआईआर पर।

विनोद नागर उज्जैन में साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित

डिप्टी सीएम बोले- अस्पतालों में पुरानी बिल्डिंग के कारण चूहों की समस्या

भोपाल। राजधानी के वरिष्ठ लेखक, पत्रकार, समीक्षक और स्तंभकार विनोद नागर को उज्जैन में साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। श्री मौनतीर्थ हिन्दी विद्यापीठ द्वारा आयोजित पाँचवे राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्हें यह सारस्वत सम्मान प्रदान किया गया। समारोह में महामंडलेश्वर डॉ. सुमनानंद गिरि सहित देश के विभिन्न भागों से आये लेखक एवं साहित्यकार उपस्थित थे।

इस अवसर पर मध्य प्रदेश नागर ब्राह्मण परिषद की उज्जैन शाखा के अध्यक्ष विजय शर्मा एवं डॉ. ललित नागर के नेतृत्व में नागर ब्राह्मण समाज की ओर से भी श्री नागर का अभिनंदन किया गया। अपने सम्मान के उत्तर में श्री नागर ने कहा कि सम्मान कभी छोट या बड़ा नहीं होता बल्कि सम्मानित होने के बाद लेखक की



जिम्मेदारी और बढ़ जाती है तथा और बेहतर लिखने की प्रेरणा मिलती है। नागर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और दूरदर्शन केंद्र, भोपाल से संयुक्त निदेशक (समाचार) के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद पिछले एक दशक से लेखन एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं।

विवाह जब सिर्फ कागज पर रह जाए तो उसे तोड़ देना बेहतर

● तलाक के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

नई दिल्ली (एजेंसी)। शदी के 24 साल पुराने एक विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक विवाह को भंग कर दिया है। अपने इस ऐतिहासिक फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत को ऐसे विवाह को नहीं बचाए रखना चाहिए, जो सिर्फ कागज पर बचे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को यह फैसला सुनाया है। इसमें पति और पत्नी 24 वर्षों से अलग-अलग रह रहे थे। सर्वोच्च अदालत ने माना कि वैवाहिक जीवन के प्रति दंपति का दृष्टिकोण मौलिक रूप से अलग था और एक-दूसरे को समझने से लगातार इनकार किया जाना आपसी क्रूरता के समान था, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता।



लंबे समय तक अलग रहना क्रूरता- एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि बिना साथ आने की किसी उम्मीद के लंबे समय से अलग रहना, दोनों पक्षों के लिए क्रूरता के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मनमोहन और जस्टिस जॉयमाला बागजी की बेंच ने पति की याचिका को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट से पास तलाक के फैसले को बहाल कर दिया।

● विवाह को कागज पर बचाने से फायदा नहीं- इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस अदालत का यह भी नजरिया है कि वैवाहिक मुकदमा को लंबे समय तक लंबित रखने से विवाह सिर्फ कागजों में ही बचा रहता है। यह पार्टियों और समाज के हित में है कि यदि मुकदमे बहुत लंबे समय से लंबित हैं, तो पक्षों के बीच संबंध समाप्त कर दिए जाएं। नतीजतन इस अदालत की राय है कि पार्टियों को राहत दिए बिना वैवाहिक मुकदमे को अदालत में लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस केस में पति-पत्नी के वैवाहिक जीवन के प्रति दृष्टिकोण को लेकर विचार बहुत मजबूत हैं और लंबे समय से दोनों तालमेल बिठाने से इनकार कर रहे हैं। इसकी वजह से इनका बर्ताव एक-दूसरे के प्रति क्रूरता की तरह है। इस अदालत का मानना है कि दो व्यक्तियों से जुड़े वैवाहिक मामले में पति-पत्नियों के तरीके में कौन सही है और कौन गलत यह तय करना समाज या कोर्ट का काम नहीं है।

लोकसभा में 'वीबी-जी राम जी' बिल पेश

● प्रियंका बोली-सरकार को नाम बदलने की सनक

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) बिल, 2025 पेश किया। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती है। बिना चर्चा के बिना सलाह लिए विधेयक को पास न करें। इसे वापस लें। नया विधेयक पेश करें। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं, मेरे परिवार जैसे ही हैं। पूरे देश की यही भावना है। कम से कम स्थायी समिति के पास इस बिल को भेजे। कोई विधेयक किसी की निजी महत्वकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पेश नहीं होना चाहिए। और ना ही पास होना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी वीबी- जी राम जी बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी का नाम बदलना सही नहीं है।



शराबी ने खुद पर हमला किया

इंदौर। चंदन नगर थाना क्षेत्र में घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है। महिला शहनाज की शिकायत पर पुलिस ने शराबी पति मोहम्मद इश्शाद पर मारपीट और प्रताड़ना का केस दर्ज किया है। आरोप है आरोपी ने पहले खुद पर हमला कर हंगामा किया और बाद में पत्नी-बेटी से बेरहमी से मारपीट की। पुलिस के मुताबिक पीड़िता सिलाई का काम करती है। रविवार को आरोपी शराब के नशे में घर पहुंचा और बेटी को अपशब्द कहने लगा। जब मैंने उसे रोका तो मारपीट करने लगा। इसके बाद मुझे डराने के लिए खुद पर ब्लेड से हमला कर लिया। घायल अवस्था में पत्नी उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां से उसे एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया। इधर, आरोपी ने एमवाय अस्पताल में स्टाफ से विवाद किया और बिना इलाज कराए देर शाम फिर घर पहुंचा और पत्नी और बेटी के साथ जमकर मारपीट की। घटना से परेशान होकर पीड़िता थाने पहुंची और पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

स्कूटी से ढोई जा रही शराब पकड़ी

इंदौर। जिले में अवैध शराब कारोबार पर नकेल कसते हुए आबकारी विभाग ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर 15 दिसंबर को आबकारी अमले ने लालाराम नगर क्षेत्र में अवैध मदिरा परिवहन का पदार्फाश किया। कंट्रोल रूम प्रभारी देशेश चतुर्वेदी, डिटी कंट्रोलर मनोज कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक आशीष जैन की टीम ने वाहन क्रमांक एमपी-09-जेडयूक्स - 2321 को रोका। तलाशी के दौरान वाहन से 75 पाव देशी मदिरा मसाला बरामद की गई। इस मामले में आरोपी अजय पिता मोहनलाल लिखारिया निवासी भागिरथपुरा को मौके से गिरफ्तार कर धारा 34(1)(क) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। जल्त की गई शराब और वाहन की कीमत 87,950 रुपए है। आबकारी विभाग द्वारा आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहने की बात कही गई है।

महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की

इंदौर। अज्ञात कारणों के चलते पति बच्चों के साथ सो रही महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब पति उठा तो महिला फंदे पर लटकती मिली। राजेन्द्र नगर पुलिस के अनुसार, घटना बिजलपुर क्षेत्र स्थित एबीसीडी बिल्डिंग का है। यहां रहने वाली लक्ष्मी ने आत्महत्या कर ली। मृतका के पति बृजमोहन ने बताया कि सोमवार सुबह 5 बजे जब उसकी नींद खुली तो लक्ष्मी फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। घटना के समय दोनों बच्चे भी कमरे में ही सो रहे थे। वह वाहन चालक है और सोमवार को उसे काम पर जाना था। दंपति रविवार को अपने पैतृक गांव राजगढ़-ब्यावरा गए थे, जहां दादी के निधन के बाद गमी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। रात में दोनों बच्चों के साथ वापस इंदौर लौटे थे। पुलिस का कहना है कि फिलहाल आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। यह भी साफ नहीं है कि दंपति के बीच किसी प्रकार का विवाद था या फिर कोई अन्य वजह रही। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। मृतक के परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं।

देर रात ऑफिस में आग लगी

इंदौर। जंजीरवाला चौराहे के पास डायमंड कॉलोनी में स्थित चार मंजिला व्यावसायिक इमारत में देर रात अचानक आग लग गई। आग तीसरी मंजिल पर बने ऑफिस में लगी, जिससे वहां रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। घटना की सूचना मिलते ही गांधी हॉल फायर स्टेशन से दमकल की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के एएसआई सुशील दुबे के नेतृत्व में टीम ने एक घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारण पूरे भवन में धुआं फैल गया था, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया। चौकीदार की सतर्कता से समय रहते दमकल विभाग को सूचना दी जा सकी। इस आगजनी में कंप्यूटर सिस्टम, फर्नीचर और महत्वपूर्ण कागजात जल गए। फायर ब्रिगेड ने करीब 10 हजार लीटर पानी का इस्तेमाल कर आग बुझाई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। प्राथमिक रूप से आग लगने का कारण बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी निलंबित

इंदौर। जिले में प्रशासनिक अनुशासन को लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए पशु औषधालय सेंडल, जिला इंदौर में पदस्थ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी मधु रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, इंदौर सभाग नि्धारित किया गया है। जानकारी के अनुसार रावत द्वारा शासकीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच में सामने आया कि उन्होंने अनुचित तरीके से ऑनलाइन उपस्थिति (सार्थक एप) दर्ज की, वहीं भारत पशुधन एप पर कुत्रिम गंभीरता से संबंधित कार्य एवं प्रविष्टियां शून्य पाई गईं। इसके अलावा शासकीय कार्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं नियमों की अवहेलना भी उजागर हुई। इन गंभीर आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने मध्यप्रदेश सivil सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में रावत को नियम के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

पति को छोड़कर भागी महिला का प्रेमी बेवफा

निकला, वापस भगाया

पैसे और जेवर लेकर खर्च किए, ट्रेन में बैठकर रवाना किया

इंदौर। पति को छोड़कर प्रेमी के साथ गई महिला ट्रेन से वापस घर लौट आई और प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जिस प्रेमी के साथ वह पति का घर छोड़कर गई थी, वह बेवफा निकला। प्रेमी ने दो लाख रुपए, जेवर हड़पकर शोषण किया और बाद में उसे भगा दिया। इस दौरान महिला को दो-तीन बार सिमरते से भी दागा। मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर प्रेमी के खिलाफ बलात्कार सहित गंभीर धाराओं में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले पीड़िता के घर के पास ही रहता था और उसके पति का दोस्त था। इसी कारण दोनों की पहचान हुई थी। आरोपी ने एक-दो बार पीड़िता से कहा था कि वह उसे पसंद करता है और उससे बात करना चाहता है, लेकिन पीड़िता ने इसका विरोध किया। फरवरी में आरोपी ने पीड़िता को अपने कमरे पर बुलाया और शादी की बात करते हुए जबरदस्ती की। इसके बाद जब भी पीड़िता का पति काम पर जाता, आरोपी घर आकर उसके साथ कई बार संबंध बनाता रहा। आरोपी की बातों में आकर पीड़िता 26 अप्रैल को घर से भाग गई, इस दौरान वह घर से दो लाख रुपए नकद और कुछ जेवर भी ले गई।

पीथमपुर और राजस्थान ले गया- इसके बाद आरोपी उसे पहले पीथमपुर ले गया, जहां किराए पर कमरा लिया। कुछ समय बाद वह उसे सांवरिया सेंट (राजस्थान) और फिर सीहोर ले जाकर रखने लगा। इस दौरान आरोपी ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके सारे जेवर व नकदी खर्च कर दिए। जब पीड़िता ने आरोपी से अपने बच्चों के पास जाने की बात कही तो उसने कहा कि यदि शादी करनी है तो अकेले रहना पड़ेगा। इसके बाद आरोपी का व्यवहार बदल गया और वह मारपीट करने लगा। उसने एक-दो बार पीड़िता को सिमरते से दागा और धमकी दी कि यदि वह घर जाने की जिद करेगी तो उसे जान से मार देगा। एक सप्ताह से पैसे खत्म होने पर आरोपी पीड़िता से घर से रुपए लाने की जिद करने लगा। मना करने पर उसने फिर से मारपीट की। रविवार को आरोपी ने उसे सीहोर से इंदौर के लिए ट्रेन में बैठा दिया।

कृष्णबाग से चार बच्चों सहित लापता महिला का शव नर्मदा नदी में मिला

इंदौर। नर्मदा नदी में मंगलवार सुबह मोरटका के

पास कटार गांव के घाट पर पत्थरों के बीच एक महिला का शव दिखाई दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कृष्णबाग कॉलोनी से लापता हुई 35 वर्षीय प्रियंका चौरसिया के रूप में की गई।

बताया गया कि सोमवार को नर्मदा का जलस्तर अधिक होने के कारण घाट के आसपास कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा था। रात में ऑकरेश्वर डैम से पानी रोके जाने के बाद मंगलवार सुबह जलस्तर कम हुआ, तब ग्रामीणों को घाट पर पत्थरों के बीच फंसा शव दिखाई दिया। ग्रामीणों ने मोरटका चौकी प्रभारी को सूचना दी। कृष्णबाग क्षेत्र निवासी सब्जी विक्रेता सुरदलाल चौरसिया की पत्नी प्रियंका 11 दिसंबर को अपने चार बच्चों 6 वर्षीय आर्यन, 5 वर्षीय प्रियांश, ढाई वर्षीय हिमांशी और 6 माह के चौकू के साथ घर से लापता हो गई थी।

आर्यन और हिमांशी मोरटका क्षेत्र में सकुशल मिल गए थे, जबकि सोमवार को 6 माह के चौकू का शव नर्मदा में मिला था। इसके बाद से प्रियंका और प्रियांश की तलाश जारी थी। मंगलवार रात अंधेरा और बढ़ा

सराफा चौपाटी के दुकानदारों का भविष्य तय नहीं, अंतिम लिस्ट का फैसला बाकी

इंदौर। शहर के जेवरात के सराफा व्यापारी

लंबे समय से यहां बढ़ती चाट और खानपान कीअन्य दुकानों की संख्या, हो-हल्ले, दुर्व्यवहार, नियमों का पालन न करने और सराफा दुकानें बंद होने से पहले अपनी दुकान लगाने जैसी शिकायतें कर रहे थे। इसके बाद 150 में से सिर्फ 69 दुकानों को अनुमति देकर बाकी दुकानें हटा दी गईं। इस वजह से पिछले कुछ महीनों से सराफा की चाट चौपाटी विवादों का केंद्र बन गई है। इससे करीब 80 दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट आ गया जब नगर निगम ने 69 दुकानों की एक लिस्ट जारी की। इसमें कहा गया कि अब चौपाटी पर केवल यही दुकान लग सकेगी जिनका नाम इस लिस्ट में है। महापौर पुष्पमित्र भावव ने पहले घोषणा की थी कि चौपाटी का पुराना और परंपरागत रूप कायम रखा जाएगा और केवल पुरातन दुकानों को ही रखा जाएगा। क्योंकि, नगर निगम का उद्देश्य चौपाटी को उसकी धरोहर के रूप में संरक्षित करना है।

पुरानी दुकान पर भी खतरा

सराफा रात्रि चौपाटी संगठन के अध्यक्ष राम गुप्ता ने बताया की 15 से 75 सालों से जो पारंपरिक रूप से दुकान लगा रही है, ऐसी दुकानों का इस सूची में नाम शामिल किया

खजराणा गणेश मंदिर की दानपेटी खुली, 1.67 करोड़ रु की गिनती

दानपेटी से सोना-चांदी व विदेशी मुद्रा भी दान मेंनिकली

इंदौर। विश्व प्रसिद्ध खजराणा गणेश मंदिर में इन दिनों दान पेटियों को खोलकर दान राशि की गिनती का कार्य जारी है। 7 दिसंबर से शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब तक श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित 1 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। जबकि, अभी दो अन्य दान पेटियों की गिनती शेष है। मंदिर परिसर में यह कार्य कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी में किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी पंडित धर्मेन्द्र भट्ट ने बताया कि खजराणा गणेश मंदिर में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा व



क्षमता के अनुसार दान अर्पित करते हैं। परंपरा के अनुसार वर्ष में तीन बार दान पेटियां खोली जाती हैं। इस बार करीब तीन माह बाद दान पेटियां खोली गई हैं, जिनकी गिनती लगातार की जा रही है। नकद राशि के अलावा दान पेटियों से सोने-चांदी के आभूषण, विदेशी करेंसी और कई श्रद्धालुओं के पत्र भी प्राप्त हुए हैं। मंदिर समिति के अनुसार अब तक प्राप्त दान राशि को बैंक में जमा करा दिया गया है।

इंदौर में स्ट्रीट फूड वेंडर्स की ट्रेनिंग होगी, सर्टिफिकेशन व निगरानी पर ध्यान देंगे

इंदौर। सोमवार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता, उचित मानक और पूर्ण रूप से शुद्ध खाद्य सामग्री प्राप्त हो। खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों पर सख्ती हो और स्ट्रीट फूड वेंडर्स पर ध्यान दिया जाए। यह कार्रवाई लगातार अभियान चलाकर की जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि मिलावटखोरों पर अब तक दर्ज मामलों के साथ आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बताया गया कि जिले में स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों का सतत निरीक्षण एवं नमूना कार्यवाही की जा रही है। एफएएसएसएआई द्वारा प्रदत्त आरबीआईएस निरीक्षण के अनुसार हाई रिस्क प्रतिष्ठानों का प्राथमिकता से निरीक्षण किया जा रहा है। गत एक जुलाई से अभी तक 576 निरीक्षण किए तथा 1392 नमूनों को जांच के लिए लिया गया। दूध एवं दुध उत्पाद के कुल 236 नमूने लिए गए। बताया गया कि संबंधित आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए हैं। नमूनों के विश्लेषण की प्रक्रिया जारी है। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में अपर कलेक्टर रोशन राय, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

महिला के साथ एक बच्चा अभी लापता, दो बच्चे लावारिस मिले

महिला मानसिक रूप से बीमार

बच्चों के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी और बिना बताए बच्चों को लेकर घर से निकल गई थी। महिला का शव मिलने के बाद एक बच्चा अब भी लापता है। सोमवार को मोरटका क्षेत्र में नर्मदा नदी से एक बच्चे का शव बरामद हुआ था। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि महिला दो बच्चों के साथ नदी में कूदी होगी। पुलिस लापता बच्चे की तलाश में सर्व अभियान चला रही है। मोरटका चौकी प्रभारी लखन डावर का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। महिला की पहचान कर उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। उधर, मोरटका पुलिस ने जीरो पर मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई के लिए खजराणा पुलिस को केंस फारवर्ड कर दिया है।

हुआ जलस्तर होने के कारण सचं ऑपरेशन रोक दिया गया था। अब प्रियंका का शव मिलने से आशंका सच में बदल गई है। हालांकि, 5 वर्षीय प्रियांश अब भी लापता है, जिसकी तलाश के लिए गोताखोरों की मदद से नर्मदा में सघन सचं ऑपरेशन चलाया जा रहा। मामले को लेकर अब भी रहस्य बना हुआ है। पुलिस यह जांच कर रही है कि यह आत्महत्या का मामला है या फिर किसी सजिश के तहत महिला और बच्चों को मोरटका पुल से नदी में धकेला गया। प्रियंका के शव की बरामदगी के बाद सवाल और गहरे हो गए हैं। पुलिस

का कहना है कि प्रियांश के मिलने के बाद ही पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठ पाएगा। महिला के साथ गए चार में से दो बच्चों को पुलिस ने ढूंढ लिया था, जबकि एक बच्चे का शव सबसे पहले नदी में मिला। पुलिस ने गूल मैप की मदद से दो बच्चों को सुरक्षित उनके पिता तक पहुंचाया। मोरटका पुलिस चौकी के अनुसार महिला 11 दिसंबर से खजराणा थाना क्षेत्र के कृष्णबाग कालोनी में रहने वाली प्रियंका पति सुंदर दास चौरसिया (35) तीन दिन पहले बिना बताए कहीं चली गई थी। महिला मजदूरी करती थी। लापता होने के बाद परिजनों

ने उसे काफी ढूंढा, जब उसका कोई पता नहीं चला तो गुमशुदगी दर्ज कराई। रविवार को महिला अपने चार बच्चों के साथ मोरटका स्थित होटल में भोजन करते हुए दिखाई दी थी। इसके बाद वह नर्मदा पुल के आसपास नजर आई। कुछ समय बाद दो छोटे बच्चे पुल के पास लावारिस हालत में मिले, जिनकी सूचना मिलने पर मोरटका पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें चौकी ले आई। डेढ़ साल की बच्ची और छह वर्षीय बालक की उम्र कम होने के कारण परिजनों तक पहुंचना पुलिस के लिए चुनौती बन गया।

इस दौरान कांस्टेबल चेतनसिंह चौहान ने बच्चे से बातचीत कर उसके पुराने स्कूल का नाम जाना। स्कूल को गूगल पर सचं कर फोटो दिखाया गया, जिसे बच्चे ने पहचान लिया। इसके बाद गूगल मैप के जरिए आसपास की गलियों, दुकानों और दवाखानों की तस्वीरें दिखाकर बच्चे से पुष्टि कराई गई। खजराणा क्षेत्र के दवाखाने के बोर्ड पर लिखे डॉक्टर के मोबाइल नंबर से संपर्क किया गया, जिन्होंने बच्चों के पिता से पुलिस की बात करवाई। इसके बाद बच्चों के पिता मोरटका पहुंचे और दोनों बच्चों की सुपुर्दी ली।

इंस्टाग्राम की रील से नकली नोट छापने वाला एक और गिरफ्तार

इस गिरोह के चार आरोपियों को पहले ही पकड़ा गया

इंदौर। क्राइम ब्रांच ने नकली नोटों के नेटवर्क पर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 500-500 रुपये के कुल 45 नकली नोट और नोट प्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रिंटर जब्त किया है। जब्त नकली नोटों की कुल कीमत करीब 22 हजार 500 रुपये आंकी गई है। क्राइम ब्रांच के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान अंकित बुरासी, निवासी बाणगंगा के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी इंस्टाग्राम पर नकली नोट बनाने से संबंधित रील देखकर प्रभावित हुआ और काम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में इस अवैध धंधे से जुड़ गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी एक अपराधिक मामला दर्ज है। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले इसी मामले में क्राइम ब्रांच चार अन्य आरोपियों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार कर चुकी है। उनसे की गई पूछताछ में फरार चल रहे पांचवें आरोपी अंकित बुरासी का नाम सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साध्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस कर गिरफ्तारी की। डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि नकली नोटों के इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है और पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले अवैध और भ्रामक प्रलोभनों से सावधान रहें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।



बस से मूसाखेड़ी से अहमदाबाद ले जायी जा रही 90 पेटी शराब जब्त

इंदौर। शहर में आबकारी विभाग और थाने

की पुलिस लगातार अवैध शराब खरीद फरोख्त पर रोक लगाने में लगा है। इसी क्रम में विजयनगर पुलिस ने लाखों की अंग्रेजी शराब के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। थाने के उपनिरीक्षक अजय सिंह कुशवाह ने बताया कि सूचना मिली थी कि बस (एमपी 09 एक्यू 1300) जिस पर सलूजा लिखा हुआ है में अवैध सामग्री परिवहन की जा रही है। यह बस बंगाली चौराहा से रेंडिसन चौराहा की तरफ आ रही है। सूचना पर टीआई के नेतृत्व में तत्काल टीम गठित की गई। टीम ने घेराबंदी कर बस को रेंडिसन चौराहा पर रोका। तलाशी लेने पर बस की डिब्बी में अंग्रेजी में ‘जिवा 18 इसेक्वीसाइट’ का लेबल लगे हुए कई बॉक्स भरे हुए थे। बॉक्स खोलकर देखा तो अंग्रेजी शराब की बोतल मिली। इस पर बस के ड्रायवर एवं कंडक्टर से शराब का परिवहन करने के संबंध में वैध लाइसेंस-परमिट का पूछा तो उन्होंने किसी प्रकार का परमिट नहीं होना बताया।

बस के ड्राइवर, वलीनर, ट्रेवलस मालिक को गिरफ्तार किया



कार्टून खोलने पर उसमें से 90 पेटी अंग्रेजी शराब (कुल 777.6 लीटर) कीमत लगभग 7,50,000 रुपए बस को जब्त कर दोनो आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। मामले में पुलिस ने बस चालक आशीम खान निवासी डाबरी नागांव रोड़ धार, मेवाती पुरा जिला धार, कंडक्टर सलमान खान निवासी खातेगांव कन्नौद रोड़ जिला देवास को पकड़ा।

रिमांड लेकर पूछताछ होगी - दोनों

आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उक्त जिले की अगली कार्ययोजना में स्ट्रीट वेंडर्स की क्षमता वृद्धि और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी। बैठक में बताया गया कि ईट राइट चैलेंज-4 डैशबोर्ड की वर्तमान स्थिति के अनुसार इंदौर पूरे देश मे प्रथम स्थान पर है। इसके पूर्व भी ईट राइट चैलेंज-1 एवं ईट राइट चैलेंज-3 में भी इंदौर पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है।

गुणवत्ता की शिकायत आसान

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं मानकों से संबंधित शिकायतों के लिए दो टोल फी नंबर जारी किए गए हैं। अब कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत सीधे इन नंबरों पर दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा कलेक्टर के निर्देश पर प्रारंभ की गई है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी ने बताया कि शिकायत के लिए टोल फी नंबर 0731-181 तथा 0755-2840621 है। इन नंबरों पर कॉल कर उपभोक्ता खाद्य पदार्थों में मिलावट, गुणवत्ता में कमी, निर्धारित मानकों के उल्लंघन या किसी भी तरह की अनियमितता की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं।

संपादकीय

नबीन के सामने बड़ी चुनौतियां

भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अल्पज्ञात युवा नेता नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर एक बार फिर चौकाया है। बताया जाता है कि 45 वर्षीय नबीन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पसंद हैं और इसे संघ ने भी मंजूरी दी है। नितिन नबीन का परिवार परंपरागत रूप से भाजपाई है और उन्हें संगठन और सत्ता दोनों में काम करने का अनुभव है। दो साल पहले छत्तीसगढ़ विस चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटाने के रणनीतिकार नितिन नबीन ही थे। नबीन की नियुक्ति यूं तो भाजपा में तीसरी पीढ़ी को आगे लाने की नीति के तहत उठाया गया एक बड़ा और दूरगामी कदम है। लेकिन इसी के साथ आलाक़मान ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के ख्वाहिशमंद उन तमाम नेताओं को भी किनारे लगा दिया है, जिनके नाम लगातार मीडिया में चर्चा में रहे हैं। नितिन नबीन फ़िल्महाल बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। लेकिन इस बड़े दायित्व के बाद उन्हें मंत्री पद छोड़ना होगा। क्योंकि अब उनकी जिम्मेदारियां पूरे देश की हैं और दिल्ली ही उनका मुख्यालय होगा। कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा उन्हें राज्यसभा में ला सकती है। नितिन नबीन की नियुक्ति से भाजपा ने कई समीकरण साधने की कोशिश की है। पहला तो अगड़ी जातियों को साधना। नबीन कायस्थ समुदाय से हैं और यह जाति अब मोटे तौर पर भाजपा समर्थक है तथा जिसकी शिकायत यही है कि संगठन में ऊंचे पदों पर उनकी संख्या बहुत कम है। दूसरे नबीन उन बिहार से जो देश के पूर्वी हिस्से में आता है और राष्ट्रीय राजनीति में उसकी भूमिका सीमित ही रही है। तीसरे, नबीन युवा है और उन्हें कम से कम 25 साल राजनीति करनी है। माना जा रहा है कि कम उम्र होने से युवा कार्यकर्ताओं से उनका कनेक्ट अच्छा रहेगा। अब यह नबीन पर निर्भर है कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने से कैसे जोड़ते हैं और साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कैसा संतुलन बना पाते हैं। हालांकि भाजपा में कांग्रेस की तरह अनुशासनहीनता सहन नहीं की जाती। जो निर्णय एक बार हो चुका, उसे सभी को मानना पड़ता है। लेकिन नितिन नबीन के सामने खुद सिद्ध करने की पहली चुनौती तो अगले साल देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। जिनमें से दो में भाजपा सत्ता में है और दो में सत्ता पाने की आस पाले हुए हैं। मसलन असम और पुदुच्चेरी में 2026 के मार्च/अप्रैल में चुनाव होना है। असम पुदुच्चेरी में भाजपा सत्ता में है और सत्ता में फिर से वापसी उसका लक्ष्य है। नबीन के नेतृत्व में यह कैसे संभव होगा, इस पर पूरे देश की निगाहें रहेंगी। लेकिन नबीन के सामने इससे भी बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में भाजपा को सत्ता में लाना है। वहां मुकाबला ‘तुम बाल डाल तो हम पात पात’ वाली ममता बैनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से है और राज्य में भाजपा का संगठन अपेक्षित रूप से मजबूत नहीं है। ममता को हराना भाजपा और संघ की तीव्र इच्छा है। लेकिन यह तभी संभव है, जब ममता विरोधी वोटजुट हो और राज्य में बड़े पैमाने पर ऊर्ध्व साम्राज्यिक विभाजन हो, मुस्लिम वोट बड़े पैमाने पर विभाजित हो और हिंदू वोट भाजपा के पक्ष में एकजुट हो। यह असंभव नहीं तो बहुत कठिन जरूर है, क्योंकि बंगाल की जनसांख्यिकी ही ऐसी है। लेकिन नबीन बंगाल में भाजपा को सत्ता दिलाने में कामयाब रहे तो उनका राजनीतिक कद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे सवाल तो यह भी पूछा जा रहा है कि नबीन की नियुक्ति भाजपा में किसकी जीत है, लेकिन यह इसलिए बेमानी है, क्योंकि भाजपा में निर्णय कोई एक व्यक्ति नहीं करता।



कीब चार वर्षों के अंतराल के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा को भारत-रूस संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पथर माना जा रहा है। चार साल बाद जब व्लादिमीर पुतिन दिल्ली उतरे और प्रधानमंत्री मोदी खुद हवाईअड्डे पर उन्हें लेने पहुंचे, तो यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी यह उस रिश्ते की झलक थी जो दशकों से भरोसे पर खड़ा है और आज की उथल-पुथल वाली दुनिया में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। यह प्रतीकात्मकता विशेष रूप से उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब वॉशिंगटन की कड़ी नीतियाँ भारत-रूस संबंधों के विस्तार को सीमित करने की कोशिश करती दिखती हैं।

23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की थीम स्वयं इस पुराने साझेदारी के नए स्वरूप की ओर इशारा करती है जहाँ रक्षा और राजनीति के साथ-साथ आर्थिक सहयोग को और अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। पुतिन की 27 घंटे की यात्रा की असली अहमियत केवल हस्ताक्षरित समझौतों में नहीं, बल्कि उस रणनीतिक संदेश में है जो यह देती है: भारत-रूस साझेदारी अपनी गति स्वयं तय करती है और बाहरी दबावों से आसानी से विचलित नहीं होती।

शिखर बैठक में दोनों नेताओं ने साझेदारी के लगभग सभी क्षेत्रों जैसे राजनीतिक संबंधों, रक्षा सहयोग, व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा, संपर्क साधन, अंतरिक्ष, संस्कृति और शिक्षा पर व्यापक चर्चा की। वार्ता से यह साफ झलक रहा था कि दोनों देश सहयोग को एक नई दिशा और गति देना चाहते हैं।

अगर वैश्विक तस्वीर पर नज़र डालें तो यह बिल्कुल साफ दिखता है कि पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी कंपनियों के रूस से हटने से वहीं एक बड़ा आर्थिक खालीपन पैदा हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि यही खालीपन भारत के लिए अवसर बनकर सामने आया है। रूस अब ऐसे भरोसेमंद साझेदारों की तलाश में है जो उसकी अर्थव्यवस्था के नए दौर में साथ दे सकें और भारत स्वाभाविक रूप से इस सूची में सबसे ऊपर है। इसी कारण दोनों देशों ने इंडिया-रूस इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2030 का खाका अपनाया है, जो अगले कई वर्षों के लिए आपसी

पुतिन की यात्रा और रिश्तों की नई दिशा

23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की थीम स्वयं इस पुराने साझेदारी के नए स्वरूप की ओर इशारा करती है जहाँ रक्षा और राजनीति के साथ-साथ आर्थिक सहयोग को और अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। पुतिन की 27 घंटे की यात्रा की असली अहमियत केवल हस्ताक्षरित समझौतों में नहीं, बल्कि उस रणनीतिक संदेश में है जो यह देती है: भारत-रूस साझेदारी अपनी गति स्वयं तय करती है और बाहरी दबावों से आसानी से विचलित नहीं होती। शिखर बैठक में दोनों नेताओं ने साझेदारी के लगभग सभी क्षेत्रों जैसे राजनीतिक संबंधों, रक्षा सहयोग, व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा, संपर्क साधन, अंतरिक्ष, संस्कृति और शिक्षा पर व्यापक चर्चा की। वार्ता से यह साफ झलक रहा था कि दोनों देश सहयोग को एक नई दिशा और गति देना चाहते हैं।

आर्थिक सहयोग की दिशा तय करेगा। यह सिर्फ एक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि एक रोडमैप है कि भारत और रूस किन-किन क्षेत्रों में मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि अभी व्यापार का संतुलन रूस के पक्ष में झुका हुआ है और इसकी बड़ी वजह ऊर्जा आयात है। लेकिन इस बार रूसी प्रतिनिधिमंडल ने पहली बार इतने स्पष्ट रूप से भारतीय निर्यात की संभावनाओं पर भरोसा जताया। चाहे उपभोक्ता सामान हों, दवाइयाँ, कृषि उत्पाद, खाद्य सामग्री या दूरसंचार उपकरण रूस



मानता है कि भारतीय उत्पाद उसके बाजार में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

यह बात मेक इन इंडिया की वैश्विक छवि के लिए भी ताकतवर संकेत है।रूस में तेज़ी से बढ़ती कुशल श्रमिकों की मांग को देखते हुए दोनों देशों ने लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए। साथ ही भुगतान प्रणालियों को सरल बनाना, लॉजिस्टिक्स में सुधार करना, और शुल्क एवं गैर-शुल्क बाधाओं को हटाना—ये सभी मुद्दे प्रमुख रहे। दोनों देशों ने 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन बाधाओं को प्राथमिकता से सुलझाने पर सहमति जताई है। साथ ही भारत ने यूरेथियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए को जल्द निष्कर्ष तक पहुँचाने में भी गहरी रूचि दिखाई।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को देखते हुए ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग उच्च प्राथमिकता बनकर उभरा। तेल एवं गैस क्षेत्रों के अतिरिक्त, दोनों देशों ने नई परियोजनाओं जैसे रिफाईनिंग, पेट्रोकेमिकल तकनीक, ऑयलफील्ड सर्विसेज और परमाणु ऊर्जा में भारतीय निवेश की संभावनाओं पर विचार किया। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान में भी सहयोग को नए आयाम देने पर चर्चा हुई।

शिखर बैठक से पहले ही भारत ने साफ इशारा कर

सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य में उसकी सुरक्षा विकल्पों की कमी न हो। आर्कटिक और रूसी फ़ार ईस्ट जैसे क्षेत्रों में सहयोग भारत-रूस साझेदारी के अपने बेहतरीन आयाम हैं। इन क्षेत्रों में विशाल खनिज संसाधन, रेयर अर्थस और हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं और इन चीजों में भारत गहरी रूचि रखता है और जियोपॉलिटिक्स में रूस भी भारत को आर्कटिक मामलों में एक प्रमुख उभरते भागीदार के रूप में देखता है।

चार साल बाद भारत आये पुतिन की यात्रा से साफ दिखता है कि भारत और रूस के हित पहले से कहीं ज्यादा एक-दूसरे के करीब आए हैं। भारत के लिए यह एक सीधा संकेत है कि तमाम वैश्विक उता-चढ़ाव के बीच रूस अब भी वही भरोसेमंद, स्थिर और लंबी दौड़ का साझेदार है जिस पर वह दशकों से निर्भर रहा है। वैश्विक रणनीति के तौर पर रूस के लिए भी यह यात्रा बेहद अहम है क्योंकि यूक्रेन संघर्ष ने उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन भारत जैसा बड़ा, प्रभावशाली और गैर-पश्चिमी देश उसके साथ खड़ा रहे यह मॉस्को के लिए सिर्फ कूटनीतिक राहत नहीं, बल्कि उसकी वैश्विक प्रासंगिकता का प्रमाण भी है।

यह रिश्ते की वह मजबूती है जिसकी प्रतिध्वनि आने वाले वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सुनाई देती रहेगी। हाँ, यह भी सच है कि व्यापारिक असंतुलन, भुगतान से जुड़ी दिक्कतें और कुछ लंबित परियोजनाएँ आगे भी चुनौती बनकर खड़ी रहेंगी। लेकिन इन सबके बावजूद मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल एक बात बेहद स्पष्ट कर देता है भारत अब मॉस्को के साथ अपने संबंधों को सिर्फ निभाने भर तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि उन्हें और गहराई और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार दिखता है।

दरअसल, बदलती दुनिया में यह साझेदारी भारत और रूस दोनों के लिए नए अवसरों के दरवाज़े खोल रही है ऐसे अवसर जो आने वाले दशक में एशिया ही नहीं, बल्कि व्यापक वैश्विक व्यवस्था की भी अस्सर डाल सकते हैं।



भीमामी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी (काशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद के इस शीतकालीन सत्र में अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर लगातार बढ़ते जा रहे अपराध पर चिंता ज़ाहिर की है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पर तीखा हमला बोला है। उनके शब्दों में ये आयोग और ‘संवैधानिक सलाहत’ माना रह गए हैं जो दलित-आदिवासी समाज के साथ होने वाले अत्याचारों पर खानापूर्ति करते हैं, लेकिन न्याय दिलाने में पूरी तरह असफल हैं।

अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जिसे आज़ाद भारत में दलितों पर बढ़ते क्रूरतम अपराधों को देखते हुए इस अधिनियम को आवश्यकता महसूस हुई थी। संसद ने माना कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के विभिन्न उपायों के बावजूद, वे असुरक्षित बने हुए हैं। उन्हें कई नागरिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है, उन्हें विभिन्न अपराधों, अपमानों, अपमानों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।। कई क्रूर घटनाओं में, उन्हें अपनी जान और संपत्ति से वंचित किया गया है। विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से उनके विरुद्ध गंभीर अत्याचार किए जाते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो इसकी सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को हुई थी तो वह थे गरीब, दलित, शापित उन्हें लगा कि अब आज़ाद भारत में वे खुलकर सांस ले सकते हैं। एक सड़क पर चल सकते हैं, एक चौड़ाहे पर बैठ सकते हैं, एक स्कूल में साथ पढ़ सकते हैं, एक कार्यालय में साथ नौकरी कर सकते हैं। अब किसी के आगे वेवजह पर झुकने की जरूरत नहीं होगी। पर उन्हें क्या पता कि उनका सामना अब हजारों साल के मानसिक रोगियों से

एससी-एसटी पर बढ़ते अपराध और संसद में सवाल

पड़ने वाला है। ऐसे मानसिक रोगी जो किसी विशेष जाति में जन्म लेने कारण एक मनुष्य होते हुए भी दूसरे मनुष्य को दौधम दर्जे का मानव समझते हैं। वे लोग कानून के इतने सक्षम होने के बावजूद भेदभाव करने से और उनके साथ पशुओं जैसा बर्ताव करने से बाज नहीं आने वाले। वैसे तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 और 17 के अनुसार किसी भी तरह के भेदभाव का अंत

किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही मुल्क के लोगों ने किया था। फिल्म जगत में आज ‘फाइल’ बनाने की प्रक्रिया चल रही है। आज अगर इन घटनाओं पर फिल्में बने तो वे लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जो अंबेडकर को मिटाने की बात कर रहे हैं, जो उनके नाम पर सत्ता में बैठे हुए हैं शर्म से डूब कर मर जाएंगे। 30 जनवरी 1990 से लागू इस अधिनियम



कर दिया गया था। भारत के सभी नागरिकों को एक समान जीवन जीने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। परंतु फिर भी जब तमाम प्रावधानों के बावजूद दलितों का शोषण और दमन रुकने का नाम नहीं ले रहा था तब सरकार को एससी एसटी एक्ट बनाने की आवश्यकता पड़ी। आज शायद लोग भूल गए होंगे। परंतु इस एक्ट के पहले भारत में ऐसे दर्जनों दलित नरसंहार हुए थे जिसने उनके स्वतंत्रता के सभी सपनों को चकनाचूर कर दिया था। 1968 तमिलनाडु के केल्विनमण में 44 दलितों का कुचमजदूरी बहाने के मांग पर तथाकथित उच्च जातियों ने सबक सिखाते हुए जिंदा जला दिया था। इसके पश्चात् 1977 बेलछी नरसंहार, 1978 मराठीवाड़ा आंदोलन नरसंहार, 1981 देहली नरसंहार, 1984 करमचेडू नरसंहार, 1987 डालमऊ नरसंहार) जैसे दर्जनों नरसंहार हुए जिसमें दर्जनों दलितों को सबक सिखाने के नाम पर जिंदा जला दिया गया तो कहीं टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए।उनकी महिलाओं, लड़कियों का संरेआम बलात्कार किया गया, नंगा करके घुमाया गया। और यह सब आज़ाद मुल्क में

को अभी 25 वर्ष भी नहीं हुए हैं और इसे कई बार शिथिल करने और समाप्त करने का प्रयास हो चुका है। जबकि दलितों के साथ होने वाले ये बर्बर अत्याचार ना हिंदू राज्य में समाप्त हुए थे ना मुगल राज्य में न ही अंग्रेजों के शासन में और ना ही आज़ाद मुल्क में यह रुकने का नाम ले रहा है।

राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट (Ncrb) के आकड़ों के अनुसार विगत दस वर्षों में ऐसे अत्याचारों में 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।एक तरफ तो सत्ता के लिए इन दलितों को हिन्दू माना जाता है और मुस्लिमों के विरुद्ध एक होने की बात कही जाती है दूसरी तरफ उनके साथ आज भी पशुवत अपराध जारी हैं। विगत दस वर्षों में जब से देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने की राजनीति आरम्भ हुई है दलितों पर अत्याचार और बढ़े हैं।इनमें से कुछ चर्चित अपराधों ने देश और दुनियां को अचंभित किया हैं। जिनमे ऊना कांड, रोहित वेमूला की आत्महत्या, हाथरस कांड, उजाव कांड, सिंधी पेशाब कांड जैसे क्रूरतम अपराध शामिल हैं। और ये अपराधि जेल तक भी तभी पहुँचाए गए जब दलित पाटियों (जिनमे भीम आर्मी

ने प्रमुख रूप से दबाव बनाने का कार्य किया हैं) और सामाजिक आंदोलनों का सरकार पर दबाव पड़ा। ऊना कांड पर प्रधानमंत्री जी पड़ौखाली आर्यु बहते नजर आये थे तो सिंधी कांड पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पीड़ित के पैर पखारने जैसे नाटक किए थे जबकि यदि वे अपना काम ईमानदारी से करते तो इसकी उन्हें जरुरत नहीं होती । आज ऐसे अपराधों में सजा देने की स्थिति 20 व भी नहीं होती वह भी दशकों लग जाते है इन रसूखदार लोगों को सजा दिलवाने में। जिसके लिए इस परिवार को अपने रोजी-रोटी से समझौता तक करना पड़ता है ।एक ऐसा परिवार जो बमूश्किल से अपने लिए दो वक्त का भोजन जुटा पाता है उसके लिए समाज और कानून से न्याय पाने के लिए कितनी मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ती है ,सरकार को इसका अंदाजा नहीं है ।

चंद्रशेखर ने सरकार से सवाल पूछा की सरकार असुर्यथा, छुआछूत मानने वाले मानसिक रोगियों हेतु जनमाध्यमों का कैसे इस्तेमाल कर रही है और समाज पर इसका कितना प्रभाव हो रहा है? दरअसल बहुत कम लोग यह जानते होंगे की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कों जनमाध्यमों के जरिए भी समाज को जागरूक करने हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाती हैं। लेकिन सरकार गंभ निरोध, एड्स, कैसर, जैसे शारीरिक बीमारियों से निराकरण पर तो ढेरों विज्ञापन प्रसारित करना जानती हैं लेकिन हजारों साल से चले आ रहे छुआछूत, जातिगत भेदभाव जैसे मानसिक बीमारियों हेतु विज्ञापन करने से डरती हैं । मोदी जी सफाई अभियान तो चला सकते हैं लेकिन सफाई कर्म सम्मान अभियान नहीं चला सकते। सर पर मैला ढोना, खुने हाथों से मलमूत्र साफ करना ये सब अपराध भले ना हो पर करने वालों के लिए अभिशाप जरूर हैं ।

आज सरकार दलितों के मसीहा कहे जाने वाले बाबा साहब का देश भर में प्रसिमा लगावा रही है। उनके सम्मान में बड़े-बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। लेकिन यह सब तभी सार्थक माना जाएगा जब ये अमानवीय अपराध रोकने में सरकार कामयाब हो पाएगी ।

आज सरकार दलितों के मसीहा कहे जाने वाले बाबा साहब का देश भर में प्रसिमा लगावा रही है। उनके सम्मान में बड़े-बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। लेकिन यह सब तभी सार्थक माना जाएगा जब ये अमानवीय अपराध रोकने में सरकार कामयाब हो पाएगी ।

आज सरकार दलितों के मसीहा कहे जाने वाले बाबा साहब का देश भर में प्रसिमा लगावा रही है। उनके सम्मान में बड़े-बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। लेकिन यह सब तभी सार्थक माना जाएगा जब ये अमानवीय अपराध रोकने में सरकार कामयाब हो पाएगी ।

यही हो रहा है आजकल सुगम संगीत के साथ। सुगम सहज हो गया है। और इसमें भी फ़िल्मी संगीत की बात करें तो वह तो अति सुगम हो गया है। इसी वजह से उसका मनमाना और मनचाहा दुरुपयोग भी लोग कर रहे हैं। फिर कराओके ने तो सभी को गायक बना दिया है। हर कोई गा रहा है, बिना इस बात की परवाह किये कि भगवान ने उसे सुरीली और गाने लायक आवाज़ दी भी है, या नहीं। उसे तो बस गाना है। अब जो हर हाल और हर पल गाने पर उतारू हो, और हाथ के मोबाइल में कराओके हो, तो फिर किसी और चीज़ की दख़्कार कहीं रह जाती है? इधर पट से आर्केस्ट्रा चालू उधर फट से गाना। भले ही आवाज़ फटे बांस जैसी क्यों न हो। कभी कभी तो लगता है कि इनकी तुलना फटे बांस से कर के उस बेचारे बांस की भी बेइज्जती हो रही है।

हमारे देश में लोकतंत्र है, और जैसे हम में से हरेक को मतदान का अधिकार है। वैसे ही कराओके की कृपा से हरेक को गाने का अधिकार हो चला है। मौलिक अधिकार जैसा। बोले तो गाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं गा कर ही रहूँगा। सुनने वाला अपनी परवाह खुद करे। अरे वह भी कर लो भाई। पर जैसे सिगरेट कि डिब्बिया पर उसके उपयोग करने

क्या निरापद जिंदगी के लिए राजनीतिक आसरा जरूरी है?

के प्रति प्रशासनिक नुमाइंदे समर्पित ही हो। दरअसल स्थिति यहां तक विकट हो चुकी है कि तमाम तरह के नीति निगम कानून कायदों की ओट में स्वायं सिद्धि की प्रक्रिया मूर्त रूप लेती रही है। अमतौर पर हर एक नीति निगम की सुविधानुसार व्याख्या करने का चलन भी आम होता जा रहा है। काफी हद तक भ्रष्टाचार भी शिष्टाचार का स्वरूप ग्रहण करने लगा है। इसके अतिरिक्त अफसरशाही का दंश तो आम आदमी को कचोटता ही रह है।

शासकीय नुमाइंदे सही या गलत कुछ भी करें तो भी काफी हद तक सुरक्षित होते है। लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा कुछ गलत करने पर उनका राजनीतिक भविष्य ही दांव पर लगा सकता है। वैसे भी देश में लोकतंत्र है इसलिए निर्वाचित जनप्रतिनिधि हर समय जनता की अदालत के कदमरों में ही खड़े दिखाई देते है। एक तरफ वह अधिकार संपन्न होते है तो दूसरी तरफ अपनी जवाबदेही से इनकार भी नहीं कर सकते। यह अलग बात है कि कोई जनप्रतिनिधि केवल और केवल अपने राजनीतिक दल एवं उसके शीर्ष राजनेताओं से ही सीधा संपर्क रखते हो।

ऐसी स्थिति में ऐसे जनप्रतिनिधि आम आदमी के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं रखा करते। वैसे व्यवहार में देखा गया है कि ऐसे जनप्रतिनिधि का राजनीतिक जीवन काल अत्यंत अल्प हुआ करता है। इसके विपरीत जो जनप्रतिनिधि आदमी के सुख दुख के साथी बनते हैं, वे जीवन पर्यंत राजनीतिक दृष्टि से सम्मान पाते है। वैसे भले ही शासकीय कार्य में राजनीतिक हस्तक्षेप को अनुचित ठहराया जाता हो, लेकिन यही हस्तक्षेप अनेक अवसरों पर आम नागरिकों के लिए रक्षा कवच सिद्ध हुआ है। शासन- प्रशासन को अनेक अवसरों पर राजनीतिक दबाव के चलते जनहित के प्रतिकूल निर्णय वापस लेने पड़े हैं।

शासकीय नुमाइंदे एकबारगी बेहिचक आम आदमी के साथ शुष्क व्यवहार कर सकते है। लेकिन हर एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के आम नागरिकों से शुष्क व्यवहार का खामियाजा भुगतने को बाध्य होते है। उनके लिए आम नागरिकों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध रहना ही उनके राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करने में सहायक होता है। कुल मिलाकर शासकीय नुमाइंदों की नमनमा या तानाशाही का प्रतिकार करने में आम आदमी सक्षम नहीं होता। लेकिन जनप्रतिनिधि की प्रतिबद्धता आम नागरिकों के प्रति रह सकती है, जिसे नज़रअंदाज करना उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है।

सुर ना सजे तो क्यों गाऊँ मैं, आप ही बताइए

यही हो रहा है आजकल सुगम संगीत के साथ। सुगम सहज हो गया है। और इसमें भी फ़िल्मी संगीत की बात करें तो वह तो अति सुगम हो गया है। इसी वजह से उसका मनमाना और मनचाहा दुरुपयोग भी लोग कर रहे हैं। फिर कराओके ने तो सभी को गायक बना दिया है। हर कोई गा रहा है, बिना इस बात की परवाह किये कि भगवान ने उसे सुरीली और गाने लायक आवाज़ दी भी है, या नहीं। उसे तो बस गाना है। अब जो हर हाल और हर पल गाने पर उतारू हो, और हाथ के मोबाइल में कराओके हो, तो फिर किसी और चीज़ की दख़्कार कहीं रह जाती है? इधर पट से आर्केस्ट्रा चालू उधर फट से गाना। भले ही आवाज़ फटे बांस जैसी क्यों न हो। कभी कभी तो लगता है कि इनकी तुलना फटे बांस से कर के उस बेचारे बांस की भी बेइज्जती हो रही है।

हमारे देश में लोकतंत्र है, और जैसे हम में से हरेक को मतदान का अधिकार है। वैसे ही कराओके की कृपा से हरेक को गाने का अधिकार हो चला है। मौलिक अधिकार जैसा। बोले तो गाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं गा कर ही रहूँगा। सुनने वाला अपनी परवाह खुद करे। अरे वह भी कर लो भाई। पर जैसे सिगरेट कि डिब्बिया पर उसके उपयोग करने

पर स्वास्थ्य ख़राब होने की चेतावनी लिखी रहती है। वैसी चेतावनी के साथ गा लो। कि मेरा गाना सुनने से आपको सरदर्द हो सकता है। अपनी जोखिम पर सुनें !

वैसे परंपरा गत रूप से गाना बजाना महफ़िलों का काम था। पर अब तकनीक ने इसे एकाकी बना दिया है। अपना मोबाइल और अपना माईक उठाओ, ब्लू ट्यू चालू करो। और शुरू हो जाओ। जय हो कराओके देवता की। पहले गुरु परम्परा में गुरु परखते थे। अपनी कसौटी पर कसकर देखते थे, तब कहीं जा कर गाना सिखाने को राजी होते थे। बरसों की तपस्या से गायक या वादक निखरते थे। निपुण होते थे। और उसी से स्तरीय आवाजें श्रोताओं तक पहुँचती थी। और श्रोता सुनकर प्रसन्न होते थे। कहते हैं कि तानसेन अपनी गायकी में जब राग दीपक गाते थे, तब दीप प्रज्वलित हो उठते थे, और राग मल्हार से बारिश हो जाती थी। पर अब कराओके जैसी तकनीकों ने महगुरु का अवतार ले लिया है, और कहती हैं गायक भवः। अब गाना भी मेगी जैसा हो गया है। दो मिन्ट में तैयार। अब जब गायक दो मिन्ट में तैयार होते हैं तो उनका प्रभाव भी वैसा ही होगा। न दीप जलेंगे न बारिश होगी। हाँ सुनने वाले के तन मन में आग लगने की सम्भावना

से इंकार नहीं किया जा सकता है। वो बात तो आपने भी सुनी ही होगी। पर एक बार और सुन लीजिये। ऐसे ही एक गायक महोदय ने अचानक गाना बंद कर दिया। जिज्ञासुओं ने जानना चाहा कि गाना क्यों बंद कर दिया ? तो बोले गले कि वजह से, फिर पूछा क्या कि क्या तपस्या हो गई होगी ? तो वे बोले कुछ खास नहीं बस अड़ोसी पड़ोसी ने कहा है कि गाना बंद कर दो नहीं तो गला दबा देंगे। तब कहीं जानकर बंद किया है। अब आदमी सब कुछ बदल सकता है। गाना बंद कर सकता है, पर पड़ोसी नहीं बदल सकता ना। सो गाना बंद करने में ही भलाई समझी। इन दिनों गायकों की जो अनियंत्रित बाढ़ सी आई हुई है , उनमें शायद ही कोई खुद से पूछता हो कि सुर ना सजे तो क्यों गाऊँ मैं ? तो भइये गाना ही हो तो पहले खुद को जांचो परखो। किसी जानकर से मार्गदर्शन लो। सुर साधो, आवाज़ को निखरने दो। तब गाओ ताकि लोग चाब से सुनें। सग़हो! यह क्या बात हुई कि हरेक गाये हो। बचपन में एक निबंध पढ़ते थे ‘नेता नहीं नागरिक चाहिए’। अब कहना होगा कि गायक नहीं श्रोता चाहिए। तो अच्छे श्रोता बनो। गायक तो ऊपर वाला ही बनाता है।

स्वामी, सुबह सवैरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा अनिश्चित पब्लिकेशन, 121, देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई इप्पा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक

उमेश त्रिवेदी

कार्यकारी प्रधान संपादक

अजय बोकिल

संपादक (मध्यप्रदेश)

निवेदित तिवारी

स्थानीय संपादक

हेमंत पाल

प्रबंध संपादक

रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)

RNI No.: MP/HIN/ 2015/ 66040,

Mobile No.: 09893032101

Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवैरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं।

इनसे समाचार पत्र का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है।



सुशासन

ओपी सांकृत्यायन



सुशासन का संकल्प महज शासकीय चुस्ती का नाम नहीं, बल्कि यह विकास का एक समावेशी विजन है। आज देश में राजनीति की धारा और सत्ता के गणित को लोग चाहे जिस रूप में भी देखें पर सुशासन और विकास का साझा नए और बदलते भारत की शिनाख्त बन चुका है। व्यापक जन-कल्याण से जुड़ी केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं की सफलता से देश में बड़ा बदलाव आया है। आज की तारीख में भारत जहां गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम चलाने वाला दुनिया का शीर्ष राष्ट्र है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की संपन्नता के लिए उठाए गए कदमों से देश में एक नया मध्यवर्ग विकसित हुआ है। देश में सरकारों के लिए यह चुनौती है कि वह विकास को लेकर गतिमान तरीके से काम करे और जनता को इस बात के लिए आश्वस्त करे कि सरकार लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण की सिर्फ बात ही नहीं करती, बल्कि उस पर अमल भी करती है। इस लिहाज से हाल में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव और उसके नतीजे बहुत कुछ कहते हैं। सबने यह देखा कि समावेशी विकास का संकल्प अगर योजनागत लाभ के तौर पर लोगों, खासतौर पर महिलाओं तक पहुंचता है, तो जनता का भरोसा जीता जा सकता है। तारीफ करनी होगी बिहार में नीतीश सरकार के दो दशक से चले आ रहे शासन की कि उसने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए देश को विकास का नया मॉडल दिया। एक ऐसा मॉडल जिसमें महिला और युवाओं के लिए चिंता है, तो वहीं बिजली-पानी जैसी बुनियादी सहूलियतों को सुनिश्चित करने का प्रण भी है। अच्छी बात यह है कि चुनाव में अजेय रहने के बाद नीतीश सरकार इस दिशा में लगातार बड़े निर्णय ले रही है।

सरकार बनने के बाद नीतीश कैबिनेट ने पहला बड़ा निर्णय पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी-रोजगार देने के लिए एक अहम प्रशासनिक सुधार के तौर पर लिया। राज्य में पहले से कार्यरत 45 विभागों के अलावा तीन नए विभागों के गठन की मंजूरी दी गई। ये तीन नए विभाग हैं- युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग। नए विभागों के

गठन के साथ ही राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में स्पष्टता लाने के लिए तीन मौजूदा विभागों के नामों में परिवर्तन भी किया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नया नाम अब डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग का श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग तथा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का कला एवं संस्कृति विभाग होगा।

सरकारी कामकाज की दिशा और प्राथमिकता को स्पष्ट करने वाले इस बड़े निर्णय के बाद सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। यह कदम है सात निश्चय कार्यक्रमों के तीसरे संस्करण की घोषणा। गौरतलब है कि सात निश्चय कार्यक्रमों ने ही नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के साथ विकास पुरुष की यशस्विता प्रदान की। इस छवि की जन स्वीकृति कितनी बड़ी है यह हालिया चुनाव में भी दिखा। बिहार में नेतृत्व का हर विकल्प जहां उनके नाम के आगे एक बार फिर धराशायी हुआ, वहीं उनकी विकास दृष्टि की प्रासंगिकता फिर से जनता के बीच बड़े बहुमत के रूप में जाहिर हुई।

अब नीतीश सरकार अपने महत्वाकांक्षी सात निश्चय कार्यक्रमों के अब तीसरे चरण को लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने खुद इसका ऐलान

एक्स पर किया। उन्होंने बताया, ‘24 नवंबर 2005 को जब से हम लोगों की सरकार बनी, तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्षों से सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य

लिया गया है।’

सात निश्चय के तीसरे चरण का पहला निश्चय है -दोयुना रोजगार और दोगुनी आय। गौरतलब है कि 2023 में राज्य में जाति आधारित गणना के साथ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया गया था।

सरकार का लक्ष्य इस सर्वेक्षण के तहत चिह्नित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़ना तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त उत्पादों की बिक्री के लिए हाट-बाजारों को विकसित किया जाएगा। अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने के लक्ष्य का ऐलान वैसे भी पहले ही की जा चुकी है।

झारखंड जब तक बिहार के साथ था तो राज्य के विकास में औद्योगिक क्षेत्र का विनियोग खासा अहम था। पर राज्य के विभाजन के बाद इस दिशा में कोई बड़ी पहल नहीं हुई। बिहार सरकार ने इस दिशा में अपने प्रयासों को अब जमीनी सफलता में बदलना चाहती है। लिहाजा सात निश्चय-3 का दूसरा निश्चय ‘समृद्ध उद्योग- सशक्त बिहार’ है। इसके तहत राज्य में तेजी

के उद्योगों के विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। इन समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य है- बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाना, प्रदेश को विश्वस्तरीय कार्यस्थल के रूप में विकसित करना और राज्य के प्रतिष्ठित उद्यमियों तथा प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना।

बिहार में आर्थिकी का बड़ा आधार आज भी कृषि है। सात निश्चय-3 का तीसरा निश्चय इससे ही जुड़ा है। इसके तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए वर्ष 2024 से 2029 के लिए गठित चौथे कृषि रोड मैप के काम में और तेजी लाई जाएगी। साथ ही मखाना रोड मैप बनाकर मखाना के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। सात निश्चय के नए संस्करण में उन्नत शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे का विकास के सबसे लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने का प्रण लिया गया है।

नीतीश सरकार की विकास दृष्टि और घोषित प्राथमिकताओं को देखकर विकसित भारत के साथ विकसित बिहार के विजन को जमीनी यथार्थ में बदलने की प्रदेशवासियों की आकांक्षा ठोस शक्त लेने जा रही है। अगर सब कुछ वसी तरह आगे बढ़ा ले तो अगले पांच वर्षों में बिहार सर्वाधिक विकसित राज्यों की कतार में तो शामिल होगा ही, यह देश में विकास और परिवर्तन की प्रेरक मिसाल भी साबित होगा।

वर्कोकि

मनोज जानी

लेखक पत्रकार हैं।



अजोबगरीब दुनिया है यह, और उससे भी अजोब है हमारी विमानन व्यवस्था। आजकल उड़ानें रद्द होना या बेतहाशा विलंबित होना उतना ही सामान्य है, जितना सुबह उठकर चाय पीना। यह अब कोई दुर्घटना नहीं, यह एक ‘सेवा मानक’ बन चुका है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। दृश्य कुछ यूँ होता है- आप बड़ी उम्मीदों और दो महीने की एडवांस बुकिंग के साथ एयरपोर्ट पहुँचते हैं। आपके चेहरे पर छुट्टी की चमक है, और दिल में ‘समय की बचत’ का संतोष। तभी, एक मीठी-सी आवाज़ लाउडस्पीकर पर गूँजती है, जो किसी फुरिश्ते की नहीं, बल्कि ‘आपकी उड़ान अब उड़ान नहीं रही’ का संदेश बुलाने वाली ‘शहनाई’ जैसी लगती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें! फ़्लाइट संख्या XYZ-786 दिल्ली से स्वर्गलोक (क्षमा करें, मेरा मतलब मुंबई) जाने वाली, अब ‘असुविधा’ के कारण विलंबित है। विलंब का कारण... कारण मत पूछिए, बस ‘असुविधा’ है। यह तीन घंटे बाद उड़ेगी। असुविधा के लिए हमें खेद नहीं है, पर कहना हमारी मजबूरी है। तीन घंटे यह सुनकर यात्रीगण ऐसे हिलते हैं, जैसे उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा हो। पर यह तो बस ‘ट्रेलर’ है, ‘पूरी फिल्म’ अभी बाकी है।

लापरवाही का ललित कला प्रदर्शन

लापरवाही यहाँ सिर्फ़ एक शब्द नहीं, यह एक कला रूप है, जिसका प्रदर्शन एयरपोर्ट पर बड़े चाव से किया जाता है।

व्यवस्था का वजूद

आप काउंटर पर जाते हैं, जहाँ एक कर्मचारी जी अपनी डेस्क पर ‘ध्यान मुद्रा’ में बैठा/बैठी है। आप पूछते हैं, ‘सर/मैम, तीन घंटे क्यों?’ जवाब मिलता है, ‘क्या करें, विमान कल रात कहीं और उड़ गया था, अब वापस आने में समय लग रहा है।’ मतलब, विमान की ‘होमसिकनेस’ (घर की याद) के कारण हम यात्रीगण

सरोकार

डॉ. चन्द्र सोनाने

लेखक मग्न जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।



और एक बार फिर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संकल्प व्यक्त किया है कि उज्जैन में 2028 में लगने वाले सिंहस्थ में साधु-संत और श्रद्धालु शिप्रा नदी के जल में ही स्नान करेंगे। पिछली बार की तरह नर्मदा या गंभीर नदी के पानी से स्नान की नौबत नहीं आयेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्व होने पर अपनी उपलब्धियां बताते हुए यह भी कहा कि पिछले सिंहस्थ में साधु, संतों ने कहा था कि हम पतितपावन शिप्रा नदी में स्नान के लिए उज्जैन आए थे, लेकिन इसमें शिप्रा का पानी है ही नहीं । अगर नर्मदा के पानी से ही स्नान करना था तो, ओंकारेश्वर जाकर भी किया जा सकता था। सिंहस्थ में शिप्रा जल का ही महत्व है, इसलिए राज्य सरकार इस परंपरा को दोबारा जीवंत करेगी।

मुख्यमंत्री ने सही कहा पिछले 2004 के सिंहस्थ में गंभीर के पानी से साधु, संत और श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसी प्रकार 2016 के सिंहस्थ में श्रद्धालुओं को नर्मदा के पानी में स्नान करना पड़ा था। मुख्यमंत्री के संकल्प से एक बार

जब ‘हवाई’ वादे जमीन पर उतर आए

परेशान हैं।

पायलट की पहली- कभी-कभी कारण बताया जाता है, ‘पायलट अभी ड्यूटी पर नहीं आए।’ ऐसा लगता है जैसे पायलट साहब सुबह अलार्म लगाना भूल गए, या शायद उन्होंने रात को तय किया कि आज ‘वर्क फ्रॉम होम’ करेंगे, यानी आज विमान नहीं उड़ाएँगे। और एयरलाइन को इसकी खबर तब लगती है, जब 200



यात्री गेट पर खड़े होकर ‘पायलट-पायलट’ चिल्ला रहे होते हैं।

तकनीकी खराबी का तांडव: सबसे प्रिय बहाना है, ‘तकनीकी खराबी!’ यह इतना रहस्यमय कारण है कि कोई भी इसका खंडन नहीं कर सकता। क्या खराब हुआ? इंजन? टायर? या शायद कॉफी मशीन? किसी को नहीं पता! बस यह सोचिए कि आपकी सुरक्षा के लिए यह ज़रूरी है, और खुद को सांत्वना दीजिए कि कम से कम आप ज़मीन पर तो सुरक्षित हैं!

मनमानी की मिठास

विलंब और रद्द होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है मनमानी का। एयरलाइन के लिए आप यात्री नहीं, एक ‘चलती-फिरती सीट’ हैं।

कम यात्री, बड़ा झटका

अगर किसी उड़ान में 50 प्रतिशत से कम सीटें भरी हैं, तो क्या होता है? वे झट से उस उड़ान को किसी और उड़ान में ‘मर्ज’ कर देते हैं। यानी, आपकी उड़ान ‘रद्द’ हो गई, और अब आप दूसरी उड़ान के ‘बोनस यात्री’ बन गए। यह ठीक वैसा ही है, जैसे आप दो टिकट खरीदें और एक फ्री मिले, बस यहाँ पूरी वाला टिकट आपके समय और दिमाग का होता है।

कर्मचारियों का ‘वीआईपी’ व्यवहार: जब आप चिल्लाते हैं, बहस करते हैं, तो कर्मचारीगण ऐसे देखते हैं, जैसे आप उनसे उनके पुरखों की ज़मीन माँग रहे हों। उनका एक ही जवाब होता है, ‘हम कुछ नहीं कर सकते। यह मुख्यालय का फ़ैसला है।’ यह ‘मुख्यालय’ इतना रहस्यमय और शक्तिशाली होता है, जैसे यह किसी ‘काला जादू’ करने वाले गुफ़ा में बैठा हो।

यात्रियों की दुर्दशा-

इस पूरी ‘असुविधा’ की बलि चढ़ते हैं - यात्रीगण। बच्चे रो रहे हैं, क्योंकि उनकी नानी का घर अब 6 घंटे दूर हो गया है। व्यापारी परेशान हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरी मीटिंग अब ‘जूम’ पर होगी, और डील शायद हाथ से निकल चुकी होगी। बुजुर्ग यात्री थक चुके हैं, और एयरपोर्ट की प्लास्टिक वाली कुर्सियाँ उन्हें नरक का अहसास करा रही हैं। एयरलाइन आपको क्या देती है? एक रू. 200 का फूड वाउचर, जिससे आप एक कप चाय और एक सैंडविच खरीद सकते हैं। यानी, आपके 10 घंटे बर्बाद करने का मुआवज़ा - एक अधूरा नाश्ता! तो अगली बार जब आप एयरपोर्ट जाएँ, तो अपनी घड़ी नहीं, बल्कि अपना धैर्य साथ लेकर जाएँ। क्योंकि यह हवाई यात्रा अब सफ़र कम और सत्याग्रह ज़्यादा बन गई है। असुविधा के लिए धन्यवाद! (क्योंकि यहाँ खेद नहीं, बल्कि धन्यवाद कहना ही सही लगता है।)

सिंहस्थ में शिप्रा के जल में ही लगायेंगे डूबकी

फिर आस जगी है कि आगामी सिंहस्थ में साधु, संत ही नहीं बल्कि श्रद्धालु भी शिप्रा के जल से ही स्नान कर पुण्य प्राप्त कर सकेंगे।

आइये, देखते हैं कि सिंहस्थ 2028 में शिप्रा के जल से ये स्नान कैसे संभव हो सकेगा ? मां शिप्रा को निरंतर प्रवाहमान बनाएं रखने लिए सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना 614.53 करोड़ की लागत से बनाई गई है। यह परियोजना सिंहस्थ के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, जिसका कार्य मौके पर प्रारंभ हो चुका है। परियोजना में सेवरखेड़ी में बैराज का निर्माण कर मानसून के समय बैराज से 51 मिली घन मीटर जल को लिफ्ट (उद्‌हन) कर सिलारखेड़ी जलाशय में डाला जाएगा जिसके लिए सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी जलाशय का विस्तार टैंकनुमा आकृति में किया जा रहा है। सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी जलाशय की

आकृति से कोई नया डूब क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। परियोजना से वर्षों के जल का उपयोग कर संपूर्ण वर्ष जलाशय में एकत्र कर पुनः आवश्यकता अनुसार शिप्रा नदी में प्रवाहित कर शिप्रा नदी को निरन्तर प्रवाहमान बनाया है।

पिछले दिनों उज्जैन के संभागयुक्त श्री आशीष सिंह ने सिवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना का निरीक्षण किया था। इस परियोजना का 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। सिंहस्थ 2028 के ध्यान में रखते हुए सिंहस्थ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं के स्नान हेतु शिप्रा नदी का जल उपलब्ध कराना है। परियोजना पूर्ण हो जाने से शिप्रा नदी को स्वच्छ एवं निरन्तर प्रवाहमान किया जा सकेगा एवं उज्जैन शहर की आगामी पेयजल की मांग की पूर्ति की जा सकेगी। इस क्षमता का बैराज निर्माण कर, यहां से तीन मीटर व्यास

शिप्रा नदी में प्रवाहित कर शिप्रा नदी को निरन्तर प्रवाहमान बनाया है।

पिछले दिनों उज्जैन के संभागयुक्त श्री आशीष सिंह ने सिवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना का निरीक्षण किया था। इस परियोजना का 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। सिंहस्थ 2028 के ध्यान में रखते हुए सिंहस्थ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं के स्नान हेतु शिप्रा नदी का जल उपलब्ध कराना है। परियोजना पूर्ण हो जाने से शिप्रा नदी को स्वच्छ एवं निरन्तर प्रवाहमान किया जा सकेगा एवं उज्जैन शहर की आगामी पेयजल की मांग की पूर्ति की जा सकेगी। इस क्षमता का बैराज निर्माण कर, यहां से तीन मीटर व्यास

के 6.50 कि.मी. पाइप लाइन द्वारा शिप्रा नदी का जल सिलारखेड़ी जलाशय में संचित किया जाएगा। इस हेतु सिलारखेड़ी जलाशय की क्षमता 51 मी.घ.मी. तक बढ़ाई जा रही है। सिलारखेड़ी जलाशय में संचित जल 1.80 मी. व्यास की 7.00 कि.मी. लंबी पाइप लाइन द्वारा पुनः शिप्रा नदी में ग्राम कुंवारीया के समीप आवश्यकता अनुसार छोड़ा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि शिप्रा के जल को स्वच्छ रखने के लिए एक अन्य खान क्लोज डक्ट परियोजना का भी काम चल रहा है। इसमें खान नदी के दूषित जल को क्लोज डक्ट परियोजना के माध्यम शिप्रा में मिलने से रोका जायेगा। अभी हो यह रहा है कि खान नदी का दूषित पानी शिप्रा नदी में त्रिवेणी पर मिल रहा है, जिससे आए दिन शिप्रा का जल प्रदूषित हो जाता है और श्रद्धालुओं को मजबूरन उसी में स्नान करने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। यदि उनकी इस महत्वाकांक्षी सिवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना का काम समय पर पूरा हो जाता है तो शिप्रा के जल से ही साधु-संत और श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। यदि ऐसा होता है, तो मुख्यमंत्री की साधु-संतों और श्रद्धालुओं के लिए यह एक बहुत बड़ी सौगात होगी।



नर्मदापुरम जिले में एक जिला एक उत्पादन के तहत रेशम की अपार संभावना : प्रभारी मंत्री राकेश सिंह

प्रभारी मंत्री ने जिला विकास

सलाहकार समिति की प्रथम बैठक ली

नर्मदापुरम (निप्र)। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री एवं नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि एक जिला एक उत्पादन के तहत जिले में पर्यटन को लिया गया है लेकिन नर्मदापुरम जिले में रेशम की भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं, उन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं नर्मदापुरम विधायक डॉ. सीता सरन शर्मा के सुझाव पर एक जिला एक उत्पादन के तहत पर्यटन के साथ-साथ ही रेशम की भी संभावना तलाशने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह रविवार को कलेक्टर कार्यालय

के सभाकक्ष में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

प्रभारी मंत्री ने नवगठित समिति में शामिल विभिन्न क्षेत्रों के नामांकित सभी 20 सदस्यों का परिचय लिया और जिला विकास सलाहकार समिति के उद्देश्य एवं कार्य की जानकारी देते हुए बताया कि समिति जिले की जनता जनप्रतिनिधियों एवं अन्य हित धारकों की जरूरत और सुझाव के अनुसार जिले की दीर्घकालीन विकास की योजनाएं बनाएगी। जिले के परंपरागत कौशल को चिन्हित कर माननीय प्रधानमंत्री के वोकल फार लोकल के सिद्धांत के दृष्टिगत उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देते हुए जिले की समृद्धि का रोड मैप तैयार करेगी। इसके साथ ही



जिले की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासकीय योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए अपने आवश्यक सुझाव भी समय-समय पर देगी। समिति जिले में स्थानीय प्रयासों से नवाचार की योजनाओं को मूर्त रूप देगी। रोजगार, सुजन के अवसर एवं विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य के संबंध में सुझाव देगी। इसके साथ ही उद्योग, व्यापार, जल संरक्षण जल संरचनाओं के

संरक्षण, निर्यात कृषि खनिज और पर्यावरण के क्षेत्र में जिले की कार्य योजना बनाने हेतु अपने उपयोगी सुझाव देगी। प्रभारी मंत्री ने सभी सदस्यों से परिचय प्राप्त किया।

बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं नर्मदापुरम विधायक डॉक्टर सीता सरन शर्मा, सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, पिपरिया के विधायक श्री ठाकुरदास नागवंशी, सिवनी मालवा के विधायक श्री प्रेम शंकर वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राधा पटेल, नगर पालिका नर्मदापुरम की अध्यक्ष श्रीमती नीतू महेन्द्र यादव, श्रीमती प्रीति शुक्ला, कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना, पुलिस अधीक्षक श्री साई कृष्णा एस थोटा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिमांशु जैन, सहित

समिति के सदस्यगण एवं संबंधित विभाग के अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधि गण उपस्थित रहे। जिला विकास सलाहकार समिति के संबंध में जानकारी देते हुए कलेक्टर ने बताया कि समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, समिति के उपाध्यक्ष प्रभारी मंत्री और अन्य सदस्य गण में सांसद एवं विधायक गण, नगर पालिका अध्यक्ष, समस्त जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष सदस्य रहेंगे इसके साथ ही उद्योग, व्यापार, समाज सेवा चिकित्सा, प्रगतिशील किसान, विधि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले ऐसे 20 प्रतिनिधियों को समिति में सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। कलेक्टर ने बैठक में शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे हैं नवाचार एवं अनुपम प्रयोग के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा विभाग में

प्राथमिक शाला के अनुपस्थित बच्चों को पुनः शाला तक पहुंचाने के लिए सिटी बजाओ अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी है।

नील परखरू अभियान भी प्रारंभ किया गया था। जिसमें पक्षियों के लिए सकोरों में पानी एवं दाने की व्यवस्था की गई थी। एक दीपावली शेरिंग वाली अभियान भी प्रारंभ किया गया था, जिसमें गरीब बच्चों के साथ दीवाली मनाई गई थी। एक पंखा पितरों के नाम अभियान के तहत स्कूलों के लिए दानदाताओं से फनीचर प्राप्त किए गए थे। वर्तमान में मिशन परिवर्तन, 100 अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत अधिकारियों को स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, छात्रावास आवंटित किए गए हैं।

संक्षिप्त समाचार

जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में 79 कुपोषित बच्चों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण



रायसेन (निप्र)। जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में 79 कुपोषित बच्चों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण, वितरित की गई पोषण किट रायसेन, 14 दिसम्बर 2025 रायसेन जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार महिला बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समन्वित रूप से अभियान के रूप में कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में गत दिवस महिला एव बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जिला अस्पताल रायसेन में 79 कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं पोषण किट (पोषण किट में मूंगफली गुड तिल चना मुरमुरे) का वितरण किया गया। रायसेन सीएमओ सुरेखा जाटव, पीएमश्री स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय रायसेन के प्राचार्य किशोर जॉन, ई पीएचई श्री गिरीश कामते द्वारा 5-5 बच्चों को तीन माह के लिए पोषण किट की राशि दी है। इसके अतिरिक्त पत्रकार श्री अरविंद ताम्रकार द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र बरवटपुर तथा श्री कौशल शाक्य द्वारा आंगनवाड़ी कुशायरी गोद ली गई है। कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को दवाइयां का वितरण किया गया एवं माता-पिता काउंसलिंग की गई। माता को पोषण किट का उपयोग कैसे करना है वह भी बताया गया। कार्यक्रम में महिला बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बुजेश जैन, सीएमएचओ डॉ एचएन मांडे, डॉ दिलीप माण्डले , हन्रष्ट से डॉक्टर दीपाली दुबे भी उपस्थित रहें।

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री यादव



ने रायसेन में बीएलओ की ली बैठक

रायसेन (निप्र)। रविवार को श्री राजेश यादव उपमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जिले के विधानसभा क्षेत्र 142- सांची के बीएलओ की रायसेन में बैठक ली गई। बैठक में मुख्य निर्वाचन कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के अन्य अधिकारी तथा रायसेन एसडीएम श्री मनीष शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। उपमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश यादव द्वारा बीएलओ से एसआईआर की कार्यवाही की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने 80+ आयु के मतदाताओं के घर जाकर उनसे भी चर्चा की।

गौवंश की उपयोगिता को बढ़ावा देने हेतु गोबर से उत्पाद निर्माण का सतत अभियान



विदिशा (निप्र)। किसानों एवं गो-पालकों को गोवंश की उपयोगिता से अवगत कराने के उद्देश्य से श्री गोपाल गोशाला, मेहलुआ चैराहा में गोमाताओं के गोबर से विविध उपयोगी उत्पादों के निर्माण का क्रम निरंतर जारी है। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए अब देशी गोमाताओं के गोबर से सम-रानी (धूपधवन) कप तैयार किए जा रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य गोबर की उपयोगिता को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। गोशाला परिसर में महिलाओं को प्रशिक्षण देकर गोबर से निर्मित उत्पाद तैयार कर दिए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। गोबर से बने ये सम-रानी कप धार्मिक अनुष्ठानों, हवन एवं दैनिक पूजा-पाठ में उपयोगी होने के साथ-साथ पूर्णतः प्राकृतिक एवं पर्यावरण हितैषी हैं। इस प्रयास से न केवल गोवंश संरक्षण को बल मिल रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा में भी सार्थक कदम उठाया जा रहा है।

प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने 19 करोड़ की लागत की तीन सड़कों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया

प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को किश्त की राशि का वितरण किया

नर्मदापुरम (निप्र)। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री एवं नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह ने रविवार को नर्मदापुरम जिले को तीन सड़कों की सौगात दी, उन्होंने 19 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाली तीन सड़कों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के 250 हितग्राहियों को एक एक लाख रुपए की आवास राशि की किश्त का भी वितरण किया।

रविवार को जनपद पंचायत नर्मदापुरम के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने डिवाइन सिटी से बड़ी पहाड़ियों की ओर जाने वाली सड़क का, नागपुर ओल्ड हाईवे 69 मार्ग से भोपाल तिराहे तक जाने वाले मार्ग एवं परामर्षी गार्डन से डोंगरवाड़ा ग्राम तक जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा कि



विगत दो वर्ष में लोक निर्माण विभाग ने नर्मदापुरम जिले को 1100 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य के लिए प्रदान की है। उन्होंने बताया कि इसमें सबसे बड़ा मार्ग नर्मदापुरम से टिमरनी मार्ग है जो 900 करोड़ रुपए से बनने जा रहा है। प्रभारी

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि पूर्व वर्षों में सड़कों पर गड्डे, अंधेरा हुआ करता था लेकिन आज स्थिति बेहतर से बेहतर हुई है। आज देश एवं प्रदेश में ऐसा नेतृत्व है जो विकास के कार्य करके जनता के सामने अपनी रिपोर्ट कांड रखता है। हम जनता के बीच अपने कार्यों का

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बैतूल में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य का किया निरीक्षण



बैतूल (निप्र)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्तमान में चल रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत रविवार को उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल श्री संजय श्रीवास्तव ने बैतूल जिले की विधानसभा क्षेत्र 132-घोड़ाडोंगरी एवं 131-बैतूल के विभिन्न मतदान केंद्रों पर फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य का निरीक्षण कर समीक्षा

की। निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम श्री श्रीवास्तव ने विधानसभा क्षेत्र 132-घोड़ाडोंगरी के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर के कार्यालय में चल रहे पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा की।

इस अवसर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री प्रपंज आर द्वारा कार्य की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसके पश्चात उन्होंने

विधानसभा क्षेत्र 132-घोड़ाडोंगरी के मतदान केंद्र क्रमांक 130, 131, 132, 133 एवं 156 का भ्रमण कर संबंधित बीएलओ के कार्यों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। दोपहर पश्चात उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विधानसभा क्षेत्र 131-बैतूल के मतदान केंद्र क्रमांक 102, 128 एवं 134 का निरीक्षण कर बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की।

मतदान केंद्रों पर उपस्थित बीएलओ द्वारा उन्हें बीएलओ एप के माध्यम से अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं रिपीट मतदाताओं की सूची के वचन, बीएलए को सूची उपलब्ध कराने तथा कार्यवाही उपरांत विवरण को एप पर अपलोड किए जाने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इसके उपरांत विधानसभा क्षेत्र 131-बैतूल के पुनरीक्षण कार्य की समग्र समीक्षा की गई, जिसमें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डॉ. अभिजीत सिंह तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्रीमती पूनम साहू द्वारा आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की गई।

निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मकसूद अहमद, विधानसभा क्षेत्र 132-घोड़ाडोंगरी के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री प्रपंज आर, विधानसभा क्षेत्र 131-बैतूल के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी डॉ. अभिजीत सिंह, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री टी. विस्के, श्रीमती पूनम साहू, श्री श्याम सिंह डड्डे, बीएलओ सुपवाइजर श्री प्रकाशचंद भारतीय, श्री योगेश धुवें, श्री केशव सातपुते, श्रीमती अंजली सलामे, श्रीमती रजनी वाईकर सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सीहोर में साप्ताहिक जैविक प्राकृतिक हाट बाजार का हुआ शुभारंभ

सीहोर (निप्र)। कृषि विभाग द्वारा सीहोर के बाल बिहार मैदान पर आयोजित किए जा रहे जैविक कृषि उत्पादों के हाट बाजार का भाजपा जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा एवं नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रिंस राठौर ने शुभारंभ किया। यह जैविक/प्राकृतिक हाट बाजार अब प्रत्येक रविवार को नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा। हाट बाजार में जैविक अनाज, दालें, विभिन्न प्रकार की जैविक सब्जियां एवं फल, जैविक कच्ची घानी का शुद्ध तेल, वर्मी कम्पोस्ट, जैविक हल्दी, जैविक अश्वगंधा सहित अनेक जैविक उत्पाद उपलब्ध कराए गए हैं। आज आयोजित प्रथम जैविक प्राकृतिक हाट बाजार में जिले के पंजीकृत 25 जैविक कृषकों द्वारा अपने-अपने उत्पाद विक्रय के लिए लाए गए। हाट बाजार के प्रति नगरवासियों में विशेष उत्साह देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप किसानों द्वारा लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये तक का कुल विक्रय किया गया। नगर के नागरिकों के साथ-साथ विभिन्न अधिकारियों द्वारा भी जैविक उत्पाद खरीदे गए। स्थिति यह रही कि सायं 4 बजे तक अधिकांश किसानों के लगभग सभी उत्पाद विक्रय हो गए। उल्लेखनीय है कि कृषि विभाग द्वारा की जा रही यह पहल जिले में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ किसानों की आर्थ वृद्धि एवं उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए की गई है।

प्रभारी मंत्री ने मां नर्मदा प्राकट्योत्सव उत्सव 2026 की तैयारियों की समीक्षा की

नर्मदा प्राकट्योत्सव कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं को घाट तक आने जाने में कोई कठिनाई न हो, आने जाने का मार्ग सुलभ रहे: प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम जिले में मां नर्मदा प्राकट्योत्सव एवं नर्मदापुरम गौरव दिवस महोत्सव का कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया जाएगा। नर्मदा प्राकट्योत्सव एवं नर्मदापुरम गौरव दिवस के कार्यक्रम का आयोजन 24 एवं 25 जनवरी 2026 को किया जाएगा। तत संबंध में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री एवं नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि सेठानी घाट एवं अन्य घाटों पर भव्य रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम स्थल सेठानी घाट पर एवं अन्य घाटों पर इस दौरान श्रद्धालुओं को आने-जाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। श्रद्धालुओं के आवागमन का मार्ग सुलभ रहे। मार्ग पर अनावश्यक वाहनों की पार्किंग एवं जाम की स्थिति ना रहे। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मिलकर आपसी समन्वय से कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान करें।



कार्यक्रम के दौरान पार्किंग की अलग से व्यवस्था सुनिश्चित करें। ताकि वाहनों की अनावश्यक भीड़ इकट्ठी ना हो। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि सेठानी घाट पर बनाए जाने वाले जल मंच पर अतिथियों के बैठने की क्षमता का आकलन कर ही बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को आपसी समन्वय से बैठक व्यवस्था निर्धारित करने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए उन्होंने जन प्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारियों को साथ मिलकर दो से तीन बैठक अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का आगमन होगा अतः सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाए। बैठक में बताया गया कि जल मंच के सामने वाले गुर्ज पर मोडिया के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। अतिथियों को सर्किट हाउस से जल मंच तक लाने के जाने हेतु 8 सीटर बोट तैयार रहेगी। बताया गया कि इस अवसर पर दीपदान का

कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। दीपदान के कार्यक्रम में प्लास्टिक एवं प्लास्टिक रेशे के लेयर से लगे हुए दीपो का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वॉच टावर के पास लगातार अनाउंसमेंट की जाएगी एवं पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। आमंत्रण पत्र पर मां नर्मदा जयंती के स्थान पर मां नर्मदा प्राकट्योत्सव लिखा जाएगा।

बताया गया कि सेठानी घाट एवं अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था एवं यातायात पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। सेठानी घाट एवं अन्य घाटों पर किसी भी प्रकार की अग्नि घटना ना हो इसलिए तैराकों की पर्याप्त संख्या एवं जल मंच पर निरंतर विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप से सुनिश्चित की जाएगी। लोक निर्माण विभाग सभी नर्मदा घाटों की ओर जाने वाले मार्गों पर पार्किंग बैरिकेडिंग के स्थलों का चयन करेगी और तद अनुसार कार्डवार्ड सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहन फाजिल मंजिल के पास सेठ गुरु प्रसाद

स्कूल के मैदान ग्राउंड में लगाए जाएंगे। कानून व्यवस्था में लगे वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों को बैरिकेडिंग से जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक में निर्देश दिए गए कि पालतू मवेशी एवं जानवर घाटों पर भीड़ वाले स्थान में प्रवेश न करें, इसके लिए नगर पालिका का अमला विशेष ध्यान एवं निगरानी रखेंगे। सुरक्षा व्यवस्था एवं सूचनाओं के सप्रिण के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जहां पर चिकित्सा एवं एंबुलेंस सहित चिकित्सा व्यवस्था रहेगी। संपूर्ण कार्यक्रम स्थल पर होमगार्ड जवानों की तैनाती रहेगी। होमगार्ड जवान जल मंच की ओर निरंतर गश्त करेंगे तथा आकस्मिक स्थिति से बचाव के कार्य भी सुनिश्चित करेंगे। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि नर्मदा प्राकट्योत्सव एवं नर्मदापुरम गौरव दिवस के अवसर पर जिले में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति निर्यंत्रित रहे। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आपसी समन्वय से भव्य रूप से कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।

श्री अरविंद का भारत और वंदे मातरम् एक विमर्श व्याख्यानमाला का शुभारंभ

भोपाल (नप्र)। हमारा गौरव, हमारा अभिमान राष्ट्र गीत वंदे मातरम् न सिर्फ भारत को, वरन पूरी दुनिया को एक सूत्र में और सही दिशा में ले जाने की भावना से लिखा गया गीत है। इसे सिर्फ गीत कहना पर्याप्त नहीं होगा बल्कि हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत का भी पर्याय है जो हमें, हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमें किस पथ पर क्या करना चाहिए ?

यह विचार मंगलवार को श्री अरविंद सोसायटी, शाखा भोपाल के दिव्यांश रजत जयंती समारोह में विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से व्यक्त किए। श्री तोमर ने कहा कि यह गीत आज भी प्रासंगिक है और हमें आगे बढ़ने और राष्ट्र हित में लगातार प्रयत्न करने की प्रेरणा देता है। रजत जयंती समारोह में ‘ श्री अरविंद का भारत और वंदे मातरम् ’ विषय पर आयोजित विमर्श के दौरान श्री अरविंद की व्याख्या करते हुए कहा वे आध्यात्मिक पुरुष ही नहीं, कर्मयोगी भी थे। उन्होंने कहा कि श्री अरविंद का विचार था कि सिर्फ स्वतंत्रता भारत के लिए पर्याप्त नहीं होगी, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। इसी अवधारणा को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वंदे मातरम के माध्यम से देश में पूर्ण स्वराज की स्थापना का उद्घोष कर रहे हैं। इससे पहले श्री तोमर ने कहा कि भगवान ने बंकिम बाबू को वंदे मातरम लिखने की प्रेरणा दी और उसी अनुकंपा को आगे बढ़ाते हुए महर्षि अरविंद को भी अग्रसर किया।

श्री तोमर ने कहा कि अतीत में वंदे मातरम पर आपत्ति का विरोध जोरदार ढंग से नहीं किया गया। जोरदार विरोध किया होता तो गीत का विभाजन नहीं होता और भारत का विभाजन नहीं होता। श्री तोमर ने संकल्प का आख्यान करते हुए कहा कि जब तक पूर्ण वंदे मातरम साकार नहीं होगा कोई भी चैन से नहीं बैठेगा।

समाह के अध्यक्षीय वक्ता राष्ट्रीय स्वयं संघ के क्षेत्र सह

विश्व को एक सूत्र में पिरोने वाला गीत है वंदे मातरम्: तोमर



कार्यवाह हेमंत मुक्तिबोध ने अपने विचारोंतेजक उद्घोषण में आख्यान किया कि हमें वंदे मातरम को साकार रूप में अंगीकार करना होगा। वंदे मातरम का एक ही भाव है व्यक्ति के विचार, दृष्टि और कार्य समान होना चाहिए। वंदे मातरम ने करोड़ों लोगों में राष्ट्र वंदना की अलख जगाई। गीत में राष्ट्र भक्ति और अध्यात्म का अदभुत संगम है। गीत ने शताब्दी की दास्ता के खिलाफ जागरण का काम किया। यह गीत अतीत की स्मृति ही नहीं जागता बल्कि उज्ज्वल भविष्य का उद्घोष भी करता है।

श्री मुक्तिबोध ने आगे कहा कि संपूर्ण वंदे मातरम श्री अरविंद के भाव को व्यक्त करने वाला गीत है। यह बौध्द मंत्र है, देश भक्ति का, क्रांतिकारी का, नायक का, राजनीति, योगी और महर्षि का। भारत के उत्थान का अर्थ सनातन का उत्थान है। श्री मुक्तिबोध ने कहा कि वंदे मातरम के एक चरण में जन है तो दूसरे चरण में मूल्य। हमें इस बात को समझना होगा कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि विभाजित गीत को अंगीकार करना पड़ा। यह



देश भक्ति का बीजमंत्र है वंदे मातरम् - मुक्तिबोध

हमारा मित्र है और कौन शत्रु ? श्री मुक्तिबोध ने वंदे मातरम की विभाजित पंक्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि जिन पंक्तियों में पुरुषों की परंपरा, एकत्ववाद, संस्कृति गूंजती थी, उन्हें छोड़ दिया गया। बल की उपासना छोड़ी, इस कारण शत्रु का हरना छोड़ दिया, जब लक्ष्मी को छोड़ तो दरिद्रता आ गयी और विद्या व धर्म को छोड़ा तो अर्थ का अर्थ नहीं किया। इस अवसर पर विशेष अतिथि भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा के विधायक भगवानदास सबनानी ने कहा कि हमें श्री अरविंद के बहुआयामी व्यक्तित्व को समझना होगा और वंदे मातरम के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन की अलख जगाने या यूँ कहें वंदे मातरम को आजादी का मंत्र स्थापित करने की उनकी प्रेरणा आज भी प्रासंगिक है। कार्यक्रम में मप्र के मुख्यमंत्री के

सांस्कृतिक सलाहकार श्री श्रीराम तिवारी विशेष रूप से उपस्थित थे। श्री अरविंद सोसायटी की भोपाल शाखा के अध्यक्ष श्री उमेश त्रिवेदी ने अपने स्वागत भाषण में श्री अरविंद के विचारों और वंदे मातरम को आंदोलन बनाने की यात्रा पर प्रकाश डाला। मध्यप्रदेश चेटर के अध्यक्ष मनोज शर्मा ने विषय प्रबोधन किया और श्री अरविंद के बाल्यकाल से लेकर अवसान तक की कई स्मृतियों का उल्लेख किया। सोसायटी के सदस्य श्री आरआर त्रिपाठी ने अपने पिता स्वर्गीय श्री राजाराम त्रिपाठी द्वारा 25 वर्ष पहले श्री अरविंद पर लिखी कविता का पाठ किया। कार्यक्रम के आरंभ में अतिथियों ने श्री माँ और श्री अरविंद के चित्र पर माल्यापण कर दीप प्रज्ज्वलन किया। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन सोसायटी के सचिव सतीश चित्तवार ने किया।

प्रदेश के 7227 श्रमिक हितग्राहियों को दिया 160 करोड़ रुपए का संबल

श्रमिक मप्र को गढ़ने वाले सच्चे सेवक, इनकी मेहनत ही विकास की है बुनियाद: मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार हर उस जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, जो इसके वास्तविक हकदार हैं। हमारी सरकार गरीब, लाचार, श्रमिक, निराश्रित और जरूरतमंद नागरिकों को सेह, अपनत्व, स्वावलंबन और आर्थिक सहायता का संबल देती रहेगी। प्रदेश की जनता के सुख-दुख में सरकार हमेशा साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संख्यल 2.0) योजना के तहत सहायता राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के 55 जिलों के 7227 संख्यल हितग्राहियों के बैंक खाते में 160 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस योजना के प्रारंभ वर्ष 2018 से लेकर अब तक 7.76 लाख प्रकरणों में 7383 करोड़ रुपए की सहायता राशि जरूरतमंद हितग्राहियों को दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संबल योजना श्रमिकों के कठिन समय की सच्ची साथी है। सरकार हर परिस्थिति में श्रमिकों के साथ खड़ी है। संबल योजना सिर्फ आर्थिक सहायता का जरिया ही नहीं, यह सरकार और श्रमिकों के बीच आपसी भरोसे का रिश्ता भी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि समय के साथ श्रम के स्वरूप भी बदले हैं। हमारी सरकार ने गिंग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को असंगठित श्रमिक का दर्जा दिया है। एक मार्च 2024 से इन्हें भी संबल योजना के दायरे में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 1400 से अधिक गिंग वर्कर्स पंजीकृत किए गए हैं। गरीबों



और श्रमिकों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हमने संबल हितग्राहियों को आयुष्मान भारत योजना से भी जोड़ दिया है। इससे उन्हें भी 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है। साथ ही 25 लाख से अधिक नए ई-श्रमिक परिवारों को राशन पात्रता देकर उन्हें भी निःशुल्क राशन का लाभ दिया गया है। गर्भवती बहनों के लिए भी सरकार बेहद संवेदनशील है। गर्भावस्था के दौरान उन्हें काम पर न जाना पड़े और उन्हें पोषण की कमी न हो, इसी उद्देश्य से ऐसी बहनों को 16 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब पत्थर तोड़ने वाले, ईंट बनाने वाले, पापड़ अचार बनाने वाले, खाना बनाने वाले, घरों में काम करने वाले मजदूर या तेंदूपता बीनने वाले सभी श्रमिक और उनके परिवार इस योजना से जुड़कर आर्थिक मदद पा रहे हैं। साथ ही प्रदेश की कुशल श्रम शक्ति को सहकारिता के माध्यम

से आगे बढ़ाने के लिए हमने ‘श्रमणा’ जैसी योजनाएं भी शुरू की हैं, जिससे श्रमिक वर्ग आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर गरीब और श्रमिक वर्ग के साथ हर कदम पर खड़ी है। कोई भी श्रमिक परिवार खुद को असहाय न समझे। श्रमिक भाई सरकार की सभी सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठावें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में कठिनाई कभी बताकर नहीं आती। ऐसी स्थिति में जमा-पूजी (पैसा) ही हमें संबल देता है। राज्य सरकार सभी श्रमिक परिवारों के हर मुश्किल वक में साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि संबल योजना सभी को एक माला की तरह साथ जोड़कर रखती है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल कार्यक्रम में अमरकंटक से वरुंचल शामिल होकर कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में आज संख्यल योजना के अंतर्गत 7वीं बार हितग्राही परिवारों को राशि

अंतरित की जा रही है। संबल योजना के अंतर्गत अब तक 1.83 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने पंजीयन कराया है, जबकि संबल 2.0 में 43 लाख लोगों ने पंजीयन किया है। राज्य सरकार ने पूर्व की सरकार का बैंकलॉग भी खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब श्रम विभाग इस स्थिति में आ चुका है कि किसी भी संबल प्रकरण में हम मात्र 60 दिन के अंदर हितग्राही को भुगतान कर सकते हैं। यही हमारी दो साल की बड़ी उपलब्धि है।

कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री नीरज मंडलोई, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक सिंह, सचिव श्रम श्री रघुराज एम.आर., सचिव म.प्र. असंगठित श्रष्टी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल श्री बंसत कुरें सहित अधिकारी उपस्थित थे। जिलों से जनप्रतिनिधि एवं संबल हितग्राहियों ने वीसी के माध्यम से कार्यक्रम में शिरकत की।

उल्लेखनीय है कि संख्यल योजना श्रमिक एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में उभरी है। योजना के तहत महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 16 हजार रुपए दिए जाते हैं, वहीं श्रमिकों के बच्चों की उच्च शिक्षा का पूरा शिक्षण शुल्क भी राज्य सरकार वहन करती है। सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने वाली इस योजना ने लाखों परिवारों की जिंदगी में भरोसे की रोशनी जगाई है। संबल योजना के सभी पंजीकृत हितग्राही 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज भी प्राप्त कर रहे हैं। यह योजना आज आर्थिक सहायता का माध्यम होने के साथ श्रमिक परिवारों के लिए सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का भरोसा भी बन चुकी है।

सतना (नप्र)। सतना जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की लापरवाही से थैलेसीमिया से पीड़ित 4 बच्चों को एचआईवी पॉजीटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। जिसमें 2 बच्चों की रिपोर्ट एचआईवी पॉजीटिव आई। मामला चार महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसका खुलासा अब हुआ है।

चारों बच्चों की उम्र 8 से 11 साल के बीच है। थैलेसीमिया से पीड़ित इन बच्चों को नियमित रूप से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। आईसीटीसी में कराई गई जांच में यह सामने आया कि पहले सभी बच्चे एचआईवी नेगेटिव थे, लेकिन बाद की जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजीटिव आई। इसके बाद संक्रमण के स्रोत को लेकर जांच शुरू की गई।

बार-बार ट्रांसफ्यूजन में ज्यादा खतरा- ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. देवेंद्र पटेल ने बताया कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को कई बार ब्लड चढ़ाया जाता है। किसी बच्चे को 70, किसी को 80 और किसी को 100 बार तक ट्रांसफ्यूजन हो चुका है। ऐसे मामलों में एचआईवी संक्रमण का जोखिम अधिक रहता है। इसी आधार पर यह जांच की जा रही है कि संक्रमण किस ट्रांसफ्यूजन के दौरान हुआ।

अलग-अलग जगहों से लिया गया था ब्लड- डॉ. पटेल के अनुसार, इन बच्चों को केवल



जिला अस्पताल से ही नहीं, बल्कि बिरला अस्पताल (रोवा) और मध्यप्रदेश के अन्य जिलों से भी ब्लड उपलब्ध कराया गया था। ऐसे में सभी संबंधित ब्लड डोनरों की पहचान कर जांच की जा रही है। बच्चों के माता-पिता की भी जांच कराई गई है और वे एचआईवी नेगेटिव पाए गए हैं।

ब्लड लेने से पहले तय मानक अपनाए जाते हैं- डॉ. देवेंद्र पटेल ने बताया कि ब्लड डोनेशन के लिए तय मानकों का पालन किया जाता है। केवल उन्हीं डोनरों से ब्लड लिया जाता है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक, वजन कम से कम 45 किलो और हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से ऊपर होता है। ब्लड लेने से पहले प्राथमिक स्वास्थ्य जांच के साथ एचआईवी सहित अन्य संक्रमणों की स्क्रीनिंग की जाती है। उन्होंने बताया कि पहले रैपिड किट से जांच होती थी, जबकि अब एलाइजा तकनीक से एंटीबांडी

डिटेक्ट की जाती है। इस जांच में 20 से 90 दिन के भीतर बनने वाली एंटीबांडी का पता चलता है, लेकिन शुरुआती विंडो पीरियड में संक्रमण पकड़ में न आने की संभावना बनी रहती है। किट की सेंसिटिविटी भी जांच के दायरे में है।

डोनर ट्रेस करने में आ रही दिक्कत - ब्लड बैंक प्रबंधन के अनुसार जांच में सबसे बड़ी परेशानी गलत मोबाइल नंबर और अधूरे पते सामने आना है, जिससे डोनरों को ट्रेस करने में दिक्कत हो रही है।

अन्य मरीजों में संक्रमण की आशंका- चार बच्चों में संक्रमण सामने आने के बाद यह आशंका भी जताई जा रही है कि एचआईवी संक्रमित ब्लड अन्य मरीजों को भी चढ़ाया गया हो सकता है। ब्लड बैंक से गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को भी ब्लड दिया गया था, जिनमें से कुछ दोबारा जांच के लिए नहीं लौटे हैं।

एसआईआर-मृत, शिफटेड वोटर्स को दूढ़ने मैदान में उतरा अमला

अब तक 1.50 लाख का वेरिफिकेशन,

कलेक्टर समेत 551 अफसर-कर्मचारी जुटे

भोपाल (नप्र)। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) में ASDR यानी मृत, एक्सेट, शिफटेड, डबल और अन्य कैटेगरी के वोटर्स के वेरिफिकेशन के लिए मंगलवार को अफसरफिर से मैदान में उतरे। अब तक करीब डेढ़ लाख मतदाताओं को क्रॉस चेक करने का दावा है। मंगलवार शाम तक कुल 2 लाख 7 हजार 378 की जांच की जानी थी।

कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को 92 वोटर्स का वेरिफिकेशन करना है। भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र के ये वोटर्स हैं। जानकारी के अनुसार अनकलेक्टेबल कैटेगरी में शामिल मतदाताओं की जांच के लिए कुल 551 अधिकारी, बीएलओ और सुपरवाइजर की जिम्मेदारी तय की गई है। हर अधिकारी और कर्मचारी को बूथ का जिम्मा सौंपा गया। 15 दिसंबर को उन्होंने करीब 1.40 लाख वोटर्स का सत्यापन कर लिया, जबकि 10 हजार से अधिक आज अब तक (दोपहर डेढ़ बजे) हो चुके हैं। सभी वोटर्स की जांच नहीं होती है तो 18 दिसंबर के बाद उनके नाम हटा दिए जाएंगे। कलेक्टर सिंह ने भोपाल मध्य विधानसभा के पोलिंग बूथ नंबर-150 का जिम्मा लिया है। निगम कमिश्नर संस्कृति जैन को 104, जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी को 108, एडीएम सुमित पांडेय को 109, अंकुर मेश्राम को 106, पीसी शाक्य को 103, प्रकाश नायक के पास 101 वोटर्स की जांच का जिम्मा सौंपा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता के साथ सभी ज्वाइंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जिला अधिकारियों को भी विधानसभा के हिस्सेब से जिम्मेदारी दी गई है। वोटर्स के घरों पर जांच कर पता लगाया जा रहा है कि एसआईआर के दौरान जो जानकारी दी गई है, वह सही है या गलत? उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने बताया कि ऐसे मतदाता जो मृत, एक्सेट, शिफटेड, डबल और अन्य कैटेगरी में दर्ज हैं, उनकी लिस्ट विधानसभावार जिले की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

सीएम ने विजय दिवस पर वीर जवानों के शौर्य को किया नमन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विजय दिवस पर वीर जवानों के शौर्य को नमन और शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 16 दिसंबर, 1971 को भारतीय सेना के समक्ष पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए थे। आज का दिन हमारी भारतीय सेना के अदम्य साहस, अनुशासन और रणनीतिक दक्षता का स्वर्णिम अध्याय है। संपूर्ण राष्ट्र इस शौर्य के लिए गौरवान्वित है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण से समाप्त हुए 1971 के युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश आजाद हुआ था। इस उपलब्धि और वीर जवानों के शौर्य को नमन करने तथा शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रतिवर्ष 16 दिसम्बर का दिन, विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।



उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने जनसंपर्क संचालनालय में सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया।

राज्यपाल ने किया एम्स का भ्रमण

व्यवस्थाओं की जानकारी ली, रोगियों की कुशल क्षेम पूछी



भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने मंगलवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का भ्रमण किया। अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने रोगियों एवं उनके परिजनों से चर्चा कर कुशल क्षेम जाना। राज्यपाल श्री पटेल ने एम्स परिसर में स्वयं द्वारा पूर्व में रोपे गए पीपल के पेड़ के विकास पर हर्ष व्यक्त कर पौधे को पानी भी दिया। राज्यपाल श्री पटेल ने वर्ष 2022 में एम्स परिसर में पीपल का पौधा लगाया था। एम्स भ्रमण के दौरान वे हमेशा पौधे के रख-रखाव की जानकारी प्राप्त करते रहे। पौधे को पानी भी देते रहे हैं।

सिंगरौली (नप्र)। सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील क्षेत्र में झरकटा पहाड़ सड़क मार्ग पर सोमवार रात एक बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश से श्रमिकों को उनके घर छोड़ने आ रही एक पिकअप वाहन पहाड़ी मोड़ पर बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे में चार मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में मरने वाले तीन लोग बगडेवा गांव के थे, जबकि एक सीमावर्ती सोनभद्र जिले के जुगैल क्षेत्र का रहने वाला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में हादसे की वजह कोहरे को माना जा रहा है। मृतकों की पहचान शीलू (32), अमरपाल बैगा (36), लाल कुमार (35) और सूरज लाल बैगा (31) के रूप में हुई है। घायलों में संतोष कुमार, अमरेश कुमार पटेल और नन्हकू केवट की हालत गंभीर बताई जा रही है।

रास्ते में कोहरे के कारण हादसे की आशंका- सूचना



मिलते ही नौडिहवा चौकी प्रभारी मनोज सिंह चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितरंगी पंजवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

बीती रात घना कोहरा था और विजुअलिटी बेहद कम थी, जिसकी वजह से हादसा होने की आशंका है।